सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 68, नई दिल्ली । सोमवार, 20 मई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा ।

03 नॉन टीचिंग पदों को भरने के लिए एक्सटेंशन देने हेतु फोरम ने यूजीसी को लिखा पत्र

06 क्या वित्त मंत्री भैंसों पर भी 'विरासत कर' लगाएंगी

08 क्या कहती हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन्म कुण्डली

शहजाद आलम, विशेष परिवहन आयुक्त के द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर करते ही दिल्ली की महिलाओं को सार्वजनिक सवारी सेवा वाहनों में सुरक्षा की हो जाएगी गारंटी और साथ ही बंद हो जाएगी कई बरसों से वाहन मालिकों से हो रही लूट

पर क्या करेंगे वह एमओयू पर हस्ताक्षर, बड़ा सवाल ?
टोलवा

संजय बाटला

नई दिल्ली। महिलाओं को सार्वजनिक सवारी वाहनों में सुरक्षा की दृष्टि के प्रति **निर्भया कांड** पर भड़की जनता के गुस्से को शांत करने के लिए गठित गृह मंत्री सचिव कमेटी द्वारा और उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश उषा मेहरा द्वारा जारी दिशा निर्देश **"सार्वजनिक सवारी सेवा वाहनों में पैनिक बटन लगे होना अनिवार्य है जिससे किसी भी दुर्घटना के होने से पहले ही महिलाए सही विभाग/ स्थान को सुचित कर सहायता प्राप्त कर सुरक्षित रह सके"** जिस पर परिवहन विभाग तब से आज तक वाहन मालिकों को लूटकर अपनी 50% साझेदारी वाली कम्पनी डिम्ट्स और सरकारी राजस्व का इजाफा करवाता आ रहा है। **परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले जो भी इसे शुरु करने में रूकावटे थी वह सब अब खत्म हो चुकी है और अब सिर्फ विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम अब इस सेवा को जान बुझकर शुरु करने में देरी कर रहे हैं क्योंकि एनआईसी के साथ होने वाले एमओयू जो पिछले साल ही साइन हो जाना चाहिए था और जिस पर शहजाद आलम के विभाग की और से साइन होने है को करने में देरी कर रहे हैं।** एमओयू साइन होने के साथ ही दिल्ली के व्यवसायिक सार्वजनिक सवारी सेवा में समर्पित वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर अब तक लगे खिलौने सच में महिलाओं की सुरक्षा हेतु कार्य करने लगेंगे और वाहन मालिकों से भी इसकी निगरानी के नाम पर सालाना परिवहन विभाग की अधिकृत कम्पनी की फीस जमा होनी बंद हो जाएगी। यानी लूट का खेल बंद हो जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा की उम्मीद भी बन जाएगी पर उसके लिए शहजाद आलम द्वारा एमओयू साइन करना अनिवार्य है, अब देखते हैं कि कब एमओयू साइन होगा और वाहन मालिको से लूट बंद।

प्राधिकरण की मिलीभगत से शहर को लूट रहा पार्किंग माफिया नोएडा सेक्टर 33 आरटीओ ऑफिस में पकड़ा रहे ट्रक की पर्ची, ले रहे कई गुना दाम

परिवहन विशेष न्यूज

शहर में पार्किंग को लेकर विवाद बढ़ते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण प्राधिकरण की विवादस्पद नीतियां हैं, जिसमें सिर्फ पैसा कमाने की लालसा है और जनहित शून्य के करीब। **नोएडा के समाजसेवी एवं विलेज रेसिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रंजन तोमर द्वारा कुछ अहम सवाल प्राधिकरण पर उठाये हैं,** यह घटना जिसको हम आपकों अवगत करवा रहें हैं यह स्वयं उनके साथ घटी हुई घटना और तथ्यों पर आधारित है और जानकारी निकालने के बाद सामने आये हुए सत्य हैं।

पार्किंग माफिया प्राधिकरण और पुलिस के अधिकारियों से साठगांठ कर कार चालकों और मालिको को दे रहे है बस और ट्रक की पार्किंग चार्ज रेट से पर्चियां सेक्टर 33 आरटीओ कार्यालय के सामने की पार्किंग में खुले आम लूट चल रही है, जहाँ कारों से बस और ट्रक की पार्किंग चार्ज खुली बदमाशी से पार्किंग पर्ची दे कर ली जा रही हैं, आम जनता का पार्किंग पर्ची लेते समय उस पर ध्यान नहीं जाता हैं जब वापसी में पैसे पूछे जाते हैं तो पता चलता है की कैसी लूट चल रही है। **चालीस रुपए प्रथम लिखकर चला रखा है दूसरे नंबर की धांधली का खेल,** पर्ची पर जान बूझकर चालीस रुपए प्रथम लिखकर छोड़ दिया गया है, जिससे चालीस रुपए प्रथम घंटा अथवा प्रथम दो घंटे के बदले एक ही घंटे के चालीस रुपए वसूली की जा सके। इसके बाद प्रत्येक घंटा बीस रुपए लिए जाते हैं, इसके आलावा वहां खड़े अटेंडेंट द्वारा भी गर्मी में खड़े रहने के नाम पर अलग से पचास रुपए मांगा जाता है। दो से तीन घंटों का शुल्क दो सौ रुपए बताया जाता है जिसका गणित भी ठीक नहीं बैठता। प्राधिकरण की आखों के सामने इतने बड़े खेल में प्राधिकरण की संलिप्पता निश्चित ही संदिग्ध है। **नोएडा प्राधिकरण सीईओ को जनता के साथ की जाने वाली इस संगठित लूट पर तत्काल स्वयं से जांच कर लगाम लगाने के साथ इस कृत्य में जुड़े सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को दण्डित करना चाहिए।** पार्किंग के दामों और पर्चियों में एक रूपता लाये और पार्किंग के ठेकेदारों की शिकायत एवं उनके निस्तारण की प्रणाली को आसान बनाये अन्यथा यह लूट चलती रहेगी।

दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और परिवहन निगम जनता के लिए है या जनता को परेशान करने के लिए, बड़ा सवाल ?

हंसराज

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और परिवहन निगम ने साठ गाठ कर पिछले 10 सालो में डीटीसी के नाम से डीटीसी के लिए एक भी बस नही खरीदकर यह तो सिद्ध कर ही दिया था की जनता को सुखद, आरामदायक, विश्वसनीय और सुरक्षित सार्वजनिक सवारी सेवा देना जो किसी भी राज्य सरकार और विभाग का पहला दायित्व है उससे यह यह तीनों (दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन निगम) कोसो दूर है। जनता से इन्हे कुछ लेना देना नहीं है। इसका दूसरा बड़ा उदाहरण है भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक सवारी सेवा के वाहन खरीदने के लिए दी गई बड़ी सब्सिडी जिसको प्राप्त करके भी तीनो ने डीटीसी के नाम पर बसे नही खरीदी।

तीसरा उदाहरण डीटीसी और परिवहन विभाग के अस्थाई कांट्रैक्ट कर्मचारियों को हर चुनाव में घोषणा करने और बोलने के बाद भी स्थाई पक्का नही किया। अब जब दिल्ली परिवहन निगम के पास अपनी बसे है ही नही और जो कुछ पहले की बची हुई जनता को सेवा देने के लिए हैं उन्हें भी दिल्ली पुलिस, एवम्-अन्य को देकर सड़को पर जनता को परेशानी देने का खेल क्यों ? **दिल्ली परिवहन की सेवा न मिलने से दिल्ली की जनता हुई परेशान** दिल्ली परिवहन निगम ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में डीटीसी की बसें पुलिस ड्यूटी में भेजी जिससे दिल्ली की जनता को नौकरी ऑफिस पर जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जनता स्टैंड पर बस का इंतजार करती रह गई। क्लस्टर बसों के ड्राईवर बिना रोके अधिकतर बस स्टेंड से बस ले गए और डीटीसी की बस आई ही नहीं। ऐसे में दिल्ली की महिलाओं को फ्री सर्विस का सबब क्यों जब सड़कों से बसे ही कर रहे हों आप स्वयं गायब?

कही ऐसा तो नहीं की महिला फ्री के नाम से चल रहा पिंक पास भी कही ना कहीं शराब घोटाले का ही प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है डीटीसी का पूरा घाटा काफ़ी अर्से से दिल्ली सरकार ही भरती है और क्लस्टर कम्पनी की बसों को उनके टेंडर के अनुसार किलोमीटर रेट के अनुसार पेमेंट होती है फिर **पिंक पास के नाम पर दिया या खर्च दिखाया गया पैसा किसकी जेब में,** बड़ा सवाल पर दिल्ली सरकार, परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग और परिवहन निगम है तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे !!!

भीषण सड़क हादसों और उससे मौतों में आई कमी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस तरह हासिल की यह कामयाबी

राजधानी की सड़कों पर चालू वर्ष के दौरान भीषण सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों में कमी आई है। इसमें दिल्ली यातायात पुलिस के ठोस प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ओवर स्पीडिंग के मामलों में कमी और गलत दिशा में चलने वालों पर सख्त एक्शन के चलते भीषण हादसों में कमी देखने को मिली। इस वर्ष 15 मई तक 511 भीषण हादसे हुए हैं।

नईदिल्ली। राजधानी की सड़कों पर चालू वर्ष के दौरान भीषण सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों में कमी आई है। इसमें दिल्ली यातायात पुलिस के ठोस प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ओवर स्पीडिंग के मामलों में कमी और गलत दिशा में चलने वालों पर सख्त एक्शन के चलते भीषण हादसों में कमी देखने को मिली।

दिल्ली यातायात पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 15 मई तक 511 भीषण हादसे हुए हैं, जिसमें 518 लोगों की मौत हुई है। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 544 भीषण दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 552 लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान यातायात पुलिस ने दस सड़कों की पहचान की जहां सबसे अधिक घातक दुर्घटनाएं हुई है और वहां निगरानी बढ़ाने के साथ नियमों का कड़ाई से पालन कराया गया।

511 भीषण हादसे इस वर्ष 15 मई तक हुए

518 लोगों की 15 मई तक हादसे में हुई मौत

33 भीषण हादसे कम हुए इस वर्ष 15 मई तक पिछले साल के मुकाबले हुए

34 मौत इस वर्ष भीषण हादसों में 15 मई तक हुई कम

हादसे रोकने को गलत दिशा में चलने वालों पर कसी नकेल

गलत दिशा में चलने वालने वाहन चालक न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान भी जोखिम में डालते है। ऐसे में गलत दिशा में चलने वालों के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया गया।

30062 वाहन चालकों का चार माह में गलत दिशा में चलने पर हुआ चालान।

12,015 ज्यादा चालान इस साल एक जनवरी से

30 अप्रैल तक पिछले साल के मुकाबले किए।

67 प्रतिशत ज्यादा चालान 2023 के मुकाबले किए।

दस इन दस स्थानों पर किए गलत दिशा में चलने पर किए सबसे ज्यादा चालान

जफगढ़- 1389
सरिता विहार- 1333
भजनपुरा- 1133
पंजाबी बाग- 1093
कल्याणपुरी- 1062
कोतवाली- 1056
द्वारका- 1041
संगम विहार- 998
राजौरी गार्डन- 968
कमला मार्किट- 966

ओवर स्पीडिंग में कमी से भी मिली हादसों में राहत

भीषण हादसो का बड़ा कारण ओवर स्पीडिंग भी रहता है। ओवरस्पीडिंग में चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रह पता जिसके चलते भीषण हादसा हो जाता है। दिल्ली पुलिस ने एक जनवरी से ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया और सख्ती से स्पीड लिमिट का पालन कराया। जिसका असर भी दिखाई दिया और पिछले वर्ष के मुकाबले इसवर्ष ओवरस्पीडिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई।

816372 ओवर स्पीडिंग के मामले इसवर्ष आए 15 अप्रैल तक सामने

952367 मामले ओवर स्पीडिंग के आए थे 15 अप्रैल 2023 तक सामने

15 प्रतिशत कमी दर्ज की गई ओवर स्पीडिंग मामलों में इस वर्ष पिछले वर्ष इस अवधि में

135995 ओवर स्पीडिंग के मामले पिछले वर्ष इस अवधि की तुलना में कम आए इस वर्ष।

वालंटियरशाला : "भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने में #VocalForLocal के लिए मुखर बनें: सड़क सुरक्षा स्वयंसेवक बनें और बदलाव लाएँ" : अंकुर

हमारे जैसे विशाल और गतिशील देश में, सड़क सुरक्षा एक सर्वोपरि चिंता है जो हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। दैनिक आवागमन, चाहे काम के लिए, स्कूल के लिए, या अवकाश गतिविधियों के लिए, दुर्घटनाओं, ट्रैफिक जाम या खतरनाक सड़क स्थितियों के डर से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसे बदलने की शक्ति हममें से प्रत्येक के भीतर निहित है। स्थानीय सड़क सुरक्षा मुद्दों के बारे में मुखर और सक्रिय होकर, हम अपनी सड़कों को बदल सकते हैं और जीवन बचा सकते हैं।

त्रासदी आने से पहले कार्रवाई करें

अक्सर, हम सड़क सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी बड़ी दुर्घटना या सार्वजनिक आक्रोश का इंतजार करते हैं। इस प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसके बजाय, हमें एक सक्रिय रुख अपनाने की जरूरत है। यदि आपको कोई खतरनाक गड्ढा, खराब ट्रैफिक लाइट, या दुर्घटनाओं की संभावना वाला क्षेत्र दिखाई देता है, तो इसका दस्तावेजीकरण करें। फ़ोटो लें, सटीक स्थान नोट करें, और उचित स्थानीय अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करें। कई नगर पालिकाओं के पास ऐसी रिपोर्टों के लिए समर्पित मंच और हॉटलाइन हैं। ऐसा करके, आप संभावित दुर्घटनाओं को रोकते हैं और अपने समुदाय की भलाई में योगदान देते हैं।

स्थानीय प्राधिकारियों के साथ जुड़ें

सड़क सुरक्षा के मुद्दों को संबोधित करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक सही अधिकारियों के साथ संचार की कमी है। हम अक्सर अपनी निराशा सोशल मीडिया पर या दोस्तों के सामने व्यक्त करते हैं, लेकिन शायद ही उन लोगों को सूचित करने का महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं जो बदलाव ला सकते हैं। अपने स्थानीय यातायात विभाग, नगर निगम, या सड़क सुरक्षा समिति की पहचान करें। अपनी टिप्पणियाँ और चिंताएँ सीधे उन्हें भेजें। यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी रिपोर्टों का अनुसरण करें कि उनका समाधान किया जा रहा है। आपकी दृढ़ता समय पर कार्रवाई को प्रेरित कर सकती है और सुरक्षित सड़कों के प्रति समुदाय की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर सकती है।

शिकायतों को बदलाव में बदलें

सड़क की स्थिति के बारे में शिकायत करना आसान है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। हमारे देश को चेंजमेकर्स की जरूरत है - ऐसे व्यक्ति जो केवल समस्याएं बताकर संतुष्ट नहीं होते बल्कि समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। स्थानीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवक बनें, जागरूकता अभियानों में भाग लें और समान विचारधारा वाले नागरिकों के साथ सहयोग करें। सड़क सुरक्षा उपायों के महत्व पर खुद को और दूसरों को शिक्षित करें, और यातायात कानूनों को सख्ती से लागू करने की वकालत करें।

अपने समुदाय को सशक्त बनाएं

आपके कार्य दूसरों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपने समुदाय के भीतर सड़क सुरक्षा में सुधार के अपने अनुभव और सफलताएँ साझा करें। संदेश फैलाने के लिए सोशल मीडिया, स्थानीय मंचों और सामुदायिक बैठकों का उपयोग करें। सड़क सुरक्षा स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क बनाएं जो मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से पहचानने और संबोधित करने के लिए मिलकर काम कर सकें। किसी समुदाय का सामूहिक प्रयास अलग-अलग कार्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होता है।

कार्रवाई का आह्वान: आपके देश को आपकी ज़रूरत है

याद रखें, यह आपका देश है और इसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। हममें से प्रत्येक के पास महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति है। स्थानीय सड़क सुरक्षा मुद्दों के बारे में मुखर होकर, हम सतर्कता और जवाबदेही की संस्कृति में योगदान करते हैं। आइए बदलाव की चिंगारी जगाने के लिए अगली दुर्घटना का इंतज़ार न करें। सक्रिय रहें और अपने समुदाय में सड़क सुरक्षा की आवाज़ बनें।

साथ मिलकर, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी सड़कें सभी के लिए सुरक्षित हों। इसलिए, नेतृत्व करें, खतरों का दस्तावेजीकरण करें, उनकी रिपोर्ट करें और अपनी शिकायतों को रचनात्मक कार्रवाई में बदलें। सुरक्षित कल के लिए आज ही चेंजमेकर बनें।

वालंटियरशाला (स्कूल, कॉलेजों, संस्थानों, कॉरपोरेट्स से अधिकतम ऑनग्राउंड स्वयंसेवक बनाने की एक पहल है जो स्थानीय सड़क सुरक्षा के लिए मुखर हो सकते हैं और भारत को दुर्घटना मुक्त बनाने में सहायता कर सकते हैं। परिवहन विशेष और रोड सेफ्टी ओम्नी फाउंडेशन ने ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ के साथ मिलकर पूरे भारत में इस आंदोलन की शुरुआत की है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या किसी उद्देश्य के लिए समर्थन करना चाहते हैं, तो हमें Roadsafetysquad@gmail.com पर लिखें और हमारे मिशन #RoadAccidentFree भारत का हिस्सा बनें।

रिदमशाला ने श्री गोपाल गौशाला में सुबह-सुबह मनमोहक प्रेरणादायक पारंपरिक संगीत की पहल शुरू की

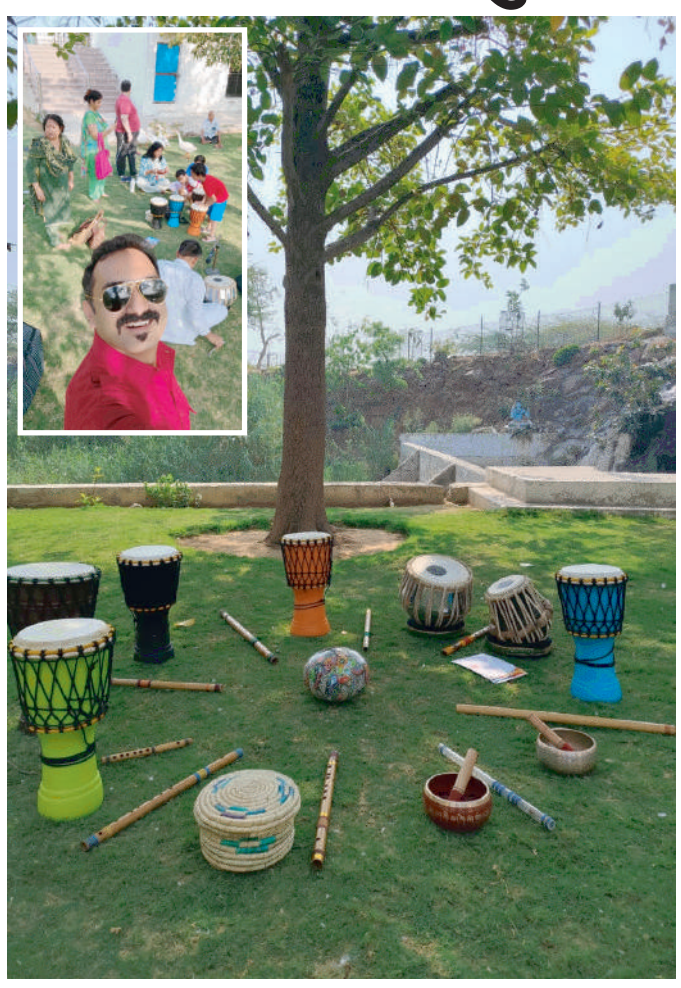

रिदमशाला ने श्री गोपाल गौशाला, फरीदाबाद के प्राकृतिक वातावरण में लाइव बांसुरी की शांत ध्वनि और लयबद्ध प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने और उसे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणादायक पहल शुरू की है। सुबह के समय स्थापित यह खूबसूरत अवधारणा एक शांत और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव प्रदान करती है जिसका उद्देश्य गौशाला पर्यटन को बढ़ावा देना और हमारे जीवन में गायों की महत्वपूर्ण भूमिका की समझ को गहरा करना है।

प्रदर्शन में प्रसिद्ध बांसुरी वादक वरुण स्वरूप, तबले पर लक्ष्य और जेम्बे पर अंकुर शामिल हैं। गौशाला के शांत वातावरण के साथ पारंपरिक भारतीय संगीत का उनका सामंजस्यपूर्ण मिश्रण एक मंत्रमुग्ध और शांतिपूर्ण माहौल बनाता है, जो सांस्कृतिक वापसी की तलाश करने वाले परिवारों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।

यह पहल न केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करती है, बल्कि भारतीय संस्कृति में गायों के महत्व पर भी जोर देती है, कृषि, डेयरी और पर्यावरण में उनके योगदान को उजागर करती है। प्रकृति और पारंपरिक मूल्यों के साथ संबंध को बढ़ावा देकर, श्री गोपाल गौशाला में रिदमशाला के सुबह के सत्र एक समृद्ध अनुभव प्रदान करते हैं जो सांस्कृतिक प्रशंसा और पर्यावरण चेतना दोनों को बढ़ावा देता है।

आगंतुकों और स्थानीय लोगों को इन सत्रों में शामिल होने, मधुर धुनों में डूबने और गौमाता से आशीर्वाद लेने के लिए समान रूप से आमंत्रित किया जाता है। यह पहल गौशाला पर्यटन की स्थायी प्रथाओं का समर्थन करते हुए भारतीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है।

स्वधर्म संदेश

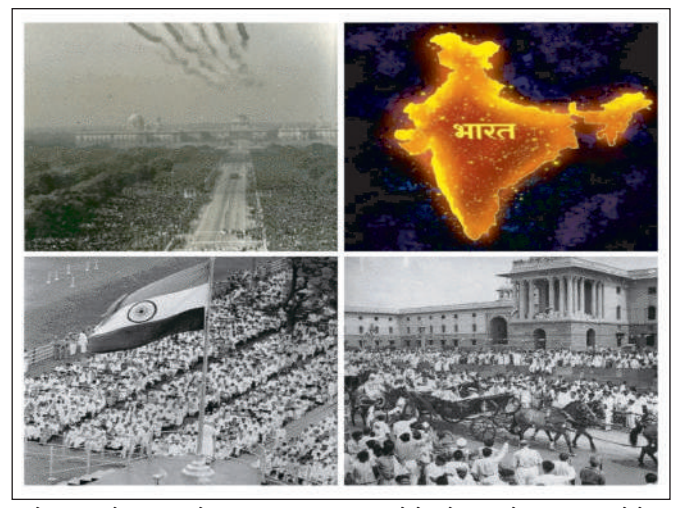

भारत को समझने के लिए भारत के लोगों को समझने की जरूरत है।

यह देश दुनिया के लिए ज्ञान और संस्कार की दृष्टिकोण से लंबे समय तक श्रेष्ठ रहा है पर 1858 के बाद जब से अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव भारतीय समाज व्यवस्था पर प्रभावी हुआ है। तब से यह देश काफी भटकाव में चला गया। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था देश की मौलिक सोच को पूरी तरह से बदल दिया अब तक की भारत की शिक्षा जीवन मूल्यों की स्थापना के साथ-साथ सामाजिक सरोकार के मूल सिद्धांत पर काम कर रही थी पर अंग्रेजी शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी तक सीमित हो गया। आज इस देश में पढ़ाई लिखाई का मकसद पढ़ लिखकर सिर्फ नौकरी प्राप्त करना रह गया है क्योंकि नौकरी में लूट की छूट होती है! अंग्रेजों ने इस देश में जिस व्यवस्था को प्रभावी किया उस व्यवस्था से निकलने वाले अधिकांश युवा की सोच अहंकारी बन गई।विनम्रता सहिष्णुता सहयोग एवं सहकारी सोच का अंग्रेजों द्वारा स्थापित ज्ञान व्यवस्था में कोई महत्व नहीं रहा। हमारे जो बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पेशा में चले गए। उन लोगों ने कम समय में अधिक से अधिक धन कमाने के सिवाय और कोई दूसरा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। ऐसी स्थिति में सामाजिक दायित्व के प्रति हमारी जिम्मेदारियां पूरी तरह से अहंकारी हो गई और शोषण दोहन दमन के सिद्धांत पर काम कर रही है। कानून का सबसे ज्यादा दुरूपयोग शासन सत्ता और व्यवस्था में बैठे हुए नेता मंत्री विधायक अफसर और कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र की मर्यादाओं को सबसे ज्यादा हानि व्यवस्था की अराजक गतिविधियों की वजह से प्रभावित हुआ है। आज देश में जितनी भी समस्याएं आपको दिखाई दे रही हैं। इसका मुख्य कारण आजादी के बाद संविधान में उचित बदलाव नहीं होना मात्र ही कारक है। संविधान सभा के कुछ नेताओं ने भारतीय आजादी अधिनियम 1935 को जो भारत को हजार वर्षों तक गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था।इसीलिए स्वीकार कर लिया था ताकि आजादी में अवरोध न रहे पर संविधान में जो बदलाव की जरूरत आजादी के तुरंत बाद थी। वह नहीं हुआ और आजादी के 65 वर्षों ने कांग्रेस ने संविधान की मूल भावना का दुरुपयोग करते हुए संविधान विरोधी अटपटे निर्णयों को प्रभावी किया। जिसकी वजह से आजादी के 65 वर्षों के बाद जब देश की जनता के हित के लिए कोई व्यक्ति सही निर्णय लेने का प्रयास कर रहा है तो उसे बहुत सारी संवैधानिक अर्चने काम करने में बाधक बन गई है। इसीलिए वर्तमान चुनाव में मोदी जी द्वारा जनता से दो तिहाई बहुमत के लिए गुहार किया जा रहा है। ताकि भारत विरोधी संवैधानिक व्यवस्था को खत्म किया जा सके पर भारत की शिक्षा में भटकाव की स्थापना के कारण देश का जनमानस जो पिछले 65 वर्षों में सिर्फ रोजी-रोटी की सीमा में सीमित हो गई और पेट परिवार से आगे सोचने की स्थिति में नहीं है। यही मुख्य समस्या है। जिसकी वजह से देश विरोधी और नफरती ताकतें देश को कमजोर करने में सफल हो रही है। जनता की सोच को सकारात्मक अस्तित्व नहीं देने की वजह से देश खतरे में है। जिन लोगों ने 65 वर्षों तक देश में शासन किया उन लोगों ने धर्म और जाति को अपने वोट तुष्टिकरण का आधार बनाया। जिसमें वह अब तक सफल हैं। आज भी इस हथकंडे के माध्यम से चुनाव में सफलता की आशा कर रहे हैं पर समय बदल चुका है। अब देश की जनता सही और गलत को समझने की स्थिति में है क्योंकि जिन लोगों को पिछले 10 वर्षों में छोटे से लेकर हर भारी समस्याओं के लिए सरकार द्वारा जो काम किया गया है। उसे भारत का हर नागरिक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित हुआ है। इसीलिए इन गलत लोगों के षड्यंत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव चुनाव की सेहत पर नहीं पड़ेगा फिर भी आने वाले दिनों में देश के अंदर देश की जनता में देश के विषय में बहुत स्पष्ट जनहित के मुद्दे पर समझ विकसित हो। इसके लिए प्रशिक्षण शिक्षण और जागरण की गतिविधियों को तीव्र गति से ताकत देने की जरूरत है।

जनहित और सरकार की नीतियों को जमीनी अस्तित्व देने के लिए सरकारी संस्थान और विधायी संस्थाओं का जनविरोधी एकाधिकार को अंकुश लगाकर जो गलतियां कानून का दुरुपयोग संस्थाएं करती है। उसे पर पूरी तरह से अंकुश के लिए सरकार को कटिबंध होने की जरूरत है। साथ-साथ कठोर कानून के तहत कट्टरता, बोलने की आजादी, भारतीयता और जनहित के मुद्दे पर प्रभावी कानून को जमीनी अस्तित्व देने की जरूरत है ताकि देश की चिंता करने वाले सही लोग देश के हित के लिए काम करने में सफल हो। गलत और अवसरवादी लोग जिस तरह से राजनीतिक उछल कूद के माध्यम से इस दल से उस दल में जाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। उस पर पूरी तरह से अंकुश लगनी चाहिए और जो आर्थिक अपराध में जुड़े हुए लोग हैं। उनके विरोध में कठोर कानून की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गलत करने वाले किसी भी स्तर के लोगों को किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिल सके। मोदी से यही आशा है। इसीलिए मोदी के प्रति हमारे जैसे लोगों की अपार सहानुभूति जुड़ी हुई है। लूट की छूट नहीं होनी चाहिए। आर्थिक अपराध पर पूरी तरह से अंकुश लगाकर देश के अंदर व्यापारिक एकाधिकार को भी खत्म करने के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है।

ब्रह्म मुहूर्त

अध्यात्म को समझना जितना मुश्किल है शायद उतना ही सहज भी है, अगर कुछ आवश्यक है तो केवल इसके मर्म को समझना। क्योंकि एक बार जब आप अध्यात्म को अपनी जीवनशैली में शामिल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके व्यक्तित्व को बदल सकता है, आपकी नीयति भी इसके द्वारा परिवर्तित हो सकती है। अध्यात्म में ब्रह्म मुहूर्त को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। और यह ब्रह्म मुहूर्त का समय मानसिक संपर्क साधने के लिए श्रेष्ठ है इस समय ध्यान करने पर दिव्य अनुभूतियों को अनुभव किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त यानि स्वयं ब्रह्मा का मुहूर्त, वही ब्रह्म जिसे इस ब्रह्मांड के रचनाकर के रूप में देखा जाता है।

आध्यात्मिक दृष्टिकोण-:

* आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्म मुहूर्त का समय को सबसे खास और महत्वपूर्ण माना गया है, अगर इस समय का सही उपयोग किया जाए तो यह ना सिर्फ आपके शरीर को सकारात्मक रूप से ऊर्जावान बनाता है बल्कि आपकी आत्मा को भी पुनः परिभाषित करने का काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह हमेशा हष्ट पुष्ट व मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, उसे बीमारियों का सामना भी नहीं करना पड़ता। सूर्य उगने से ठीक डेढ़ घंटा पहले की अवधि को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय अपना बिस्तर छोड़ देता है उसकी आयु में भी वृद्धि होती है।

श्रीकृष्ण के उपदेश-:

* भगवद गीता के अंतर्गत स्वयं श्रीकृष्ण ने इस बात का उल्लेख किया है कि वह व्यक्ति जो सही आहार-विहार यानि दिनचर्या का पालन करता है वह जीवन की परेशानियों से मुक्त रहता है। ब्रह्म मुहूर्त आपको अपनी इसी जीवनशैली में सुधार लाने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय को ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि दिन के इस समय पृथ्वी की ऊर्जाएं स्वयं मनुष्य से संपर्क साधने का प्रयत्न करती है और इस समय जागने की वजह से आप ज्यादा शांत और स्थिर होते हैं। इस वजह से आप उन ऊर्जाओं को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं।

शरीर के साथ आत्मा का संबंध-:

* ब्रह्म मुहूर्त में जागने से आपके माइंड-बॉडी-सोल में एक तरह का सामंजस्य निर्मित होता है, जो न सिर्फ आपको दिनभर के कार्यों में सहायता प्रदान करता है बल्कि आगामी जीवन में भी आपको हेल्दी और दुरुस्त रखता है। आप अपने अवचेतन मन से संपर्क साध पाते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का समय आपको मिलता है। विशेषज्ञों की राय में ब्रह्म मुहूर्त के साथ 'लॉ ऑफ अट्रैक्शन' भी जुड़ा है।

अच्छा पढ़ें व सुनें-:

* इस समय के दौरान आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन मनन करना चाहिए। आष्टांग हृदय (आयुर्वेद) के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय पढ़ने और ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे अनुकूल होता है। यह माना जाता है कि इस दौरान पढ़ी चीज कभी दिमाग से नहीं निकलती। पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक दस्तावेजों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना श्रेष्ठ होता है।

भविष्य की योजना बनाएँ-:

* जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसके पास दिनभर का बहुत समय होता है, इस अवधि में आपको दिनभर में किए जाने वाले कार्यों की योजना और रोड मैप बना सकते हैं। यह आपके कार्यों को पूरा होने में हेल्प कर सकता है।

खुद में सुधार का प्रयत्न करें-:

* कल आपसे क्या-क्या गलतियाँ हुई थी, उन्हें आज आप किस तरह सुधारेंगे और किस तरह से अपने काम करेंगे, ये सभी बातों को समझे, अपने वर्तमान का आंकलन करने के लिए यह समय सबसे बेहतरीन है। खुद के बेहतर वर्जन बनाने, अपनी वर्तमान छवि तराशने के लिए यह समय बहुत अच्छा माना जाता है।

माता पिता ईष्ट गुरु को धन्यवाद दे-:

* ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपने माता- पिता, गुरु व ईष्ट का ध्यान करना चाहिए, उन्हें मानसिक धन्यवाद देना चाहिए। माना जाता है दिन के इस समय आपकी शारीरिक ऊर्जाएं सबसे शक्तिशाली होती हैं और आप आसानी से इनका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ मानसिक संपर्क साधना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस समय का उपयोग कर सकते हैं।।

ध्यान रहे, नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग भगवान का ध्यान, नाम-जप, मंत्रोच्चारण, अध्ययन- अध्यापन, योग-प्राणायाम आदि श्रेष्ठ कार्यों में ही करना चाहिए।

स्वर्ग से कम नहीं है लक्ष्यद्वीप यहां जानें रूट से लेकर फीस तक सबकुछ

इन दिनों इंटरनेट पर हर जगह लक्षद्वीप की खूबसूरती की ही चर्चा चल रही है। इसके पीछे की वजह है पीएम नरेंद्र मोदी जो कुछ दिन पहले ही लक्षद्वीप के दौरे पर थे। यहां पर न सिर्फ वो बीच बीच में टहलें बल्कि snorkeling भी की। उन्होंने अपने इस दौरे की फोटो इंटरनेट पर शेयर की जो तुरंत वायरल हो गई। इसके बाद से जो लोग घूमने के लिए विदेश ही बेहतर समझते थे, उन्हें पता चला कि खुद के देश में भी कितनी सुंदर जगहें हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं। बस तब से ही लोगों में लक्षद्वीप के बारे में और जाने की इच्छा है। अगर आप भी लक्षद्वीप जाने का मन बन रहे हैं और जानना चाहते हैं कि वहां कैसे पहुंचे तो ये स्टोरी पढ़ लें...

लेना पड़ता है परमिट

भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक लक्षद्वीप 35 द्वीपों का एक समूह है। ये पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में लक्षद्वीप सागर के लिए ये समुद्री सीमा के तौर पर काम करता है। हालांकि यहां के सारे द्नीपों पर लोग नहीं जा सकते हैं। सिर्फ कुछ सीमित द्वीपों तक जाने के लिए ही परमिट मिल सकता है। जो भी व्यक्ति इस द्वीप का निवासी नहीं है, उन्हें अंदर प्रवेश करने के लिए संबंधित अधिकारी से परमिट हासिल करना होता है। इसकी वजह यहां के जनजातियों की रक्षा करना है।

कैसे करें परमिट के लिए आवेदन

परमिट के आवेदन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दो तरीकों से परमिट के लिए आवेदन किया जा सकता है। लक्षद्वीप टूरिज्म की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आप ये परमिट की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरु कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने, जानकारी दर्ज करने और फीस का भुगतान करने के बाद आपकी यात्रा के 15 दिन पहले परमिट ई- मेल के जरिए आपको मिल सकता है। अगर इसे ऑफलाइन ये प्रक्रिया करना चाहते हैं तो कवरत्ती में कलेक्टर के दफ्तर जाना होगा। यहां से फॉर्म हासिल करना और जरूरी जानकारियां जमा करानी होगी।

परमिट के लिए दस्तावेज और फीस

आमतौर पर परमिट की वैधता 30 दिनों की होती है, लेकिन विशेष स्थिति में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। हर आवेदक को परमिट के लिए 50 रुपये चुकाने होंगे। हालांकि 12 से 18 साल के लोगों के लिए हेरिटेज फीस 100 रुपये है। जबकि ये ही फीस 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए लोगों के लिए 200 रुपये है। परमिट के लिए पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड जैसे पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी, यात्रा के टिकट दिखाने होंगे। साथ ही पर्यटकों को भी बताना होगा कि वो कौन से होटल में ठहरने वाले हैं।

कैसे पहुंचे लक्षद्वीप

कोच्चि को लक्षद्वीप का गेटवे माना जाता है। यहां आप शिप और फ्लाइट के जरिए जा सकते हैं। कोच्चि से अगति के बीच फ्लाइट्स का सफर करीब डेढ़ घंटे का होता है। अगति और बंगारम द्वीपों पर पहुंचने के लिए कोच्चि से फ्लाइट्स लेनी होगी। अगति से कवरत्ती और कदमत के लिए अक्टूबर से मई के बीच नाव मिलती है। वहीं मॉनसून के दौरान अगति से कवरत्ती तक हेलीकॉप्टर से जाया जा सकता है।

भगवान शिव और मां पार्वती के अलावा शिवलिंग पर विराजते हैं ये देवी-देवता, आप भी लें आशीर्वाद

अनन्या मिश्रा

सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। वहीं शिवलिंग पर मौजूद अलग-अलग स्थानों की पूजा-अर्चना करने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं। शिवलिंग में मां पार्वती, भगवान शिव, गणेश-कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का स्थान होता है।

सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। वहीं शिवलिंग पर मौजूद अलग-अलग स्थानों की पूजा-अर्चना करने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं। बता दें कि शिवलिंग पर भगवान शिव के अलावा माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का स्थान माना गया है। ऐसे में शिवलिंग के इन अलग-अलग स्थानों की पूजा कर आप इनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।

अशोक सुंदरी का स्थान

पद्मपुराण के अनुसार, भगवान शिव और माता पार्वती के अलावा उनकी बेटी अशोक सुंदरी का भी उल्लेख किया गया है। बता दें कि शिवलिंग में जिस स्थान से जल बहकर निकलता है, उस स्थान को अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। बता दें कि अशोक सुंदरी की पूजा करने के लिए शुद्ध जल में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए।

वहीं शिवपुराण के मुताबिक शिवलिंग में जलाधारी के आगे की ओर पद चिन्हों में कार्तिकेय और भगवान गणेश का वास माना जाता हैं। बताया जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद पद चिन्ह के स्थान पर दोनों तरफ से 5-7 बार अपने हाथों से इस तरह दबाना चाहिए, जैसे कि आप किसी के पैर दबा रहे हैं। इस दौरान जातक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। मान्यता के अनुसार, ऐसा करने से व्यक्ति को जल्द ही संतान सुख प्राप्त होता है। वहीं अगर बच्चे को किसी तरह की बीमारी या समस्या है, तो उससे भी राहत मिलती है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं कॉलेजों के नॉन टीचिंग पदों को भरने के लिए एक्सटेंशन देने हेतु फोरम ने यूजीसी को लिखा पत्र

परिवहन विशेष न्यूज

* यूजीसी ने नॉन टीचिंग पदों को भरने के 31 मार्च 2023 तक का समय दिया था, कॉलेजों ने नहीं भरे पद।
* नॉन टीचिंग पदों को भरने के लिए कॉलेजों को एक अवसर और देने के लिए फोरम ने यूजीसी को लिखा पत्र।
* दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों में ओबीसी कोटे के सबसे ज्यादा खाली पड़े गैर शैक्षिक पदों को संबंधित कालेज के प्रिंसिपलों ने नहीं भरे।

नई दिल्ली। फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार को पत्र लिखकर बताया है कि यूजीसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागों / कॉलेजों को ओबीसी विस्तार योजना के तहत गैर शैक्षणिक पदों को भरने के लिए 31 मार्च 2023 तक का एक्सटेंशन दिया था लेकिन विभागों / कॉलेजों के प्रिंसिपल इन पदों को नहीं भर पाए। इसके बाद यूजीसी की अवर सचिव वीना मेनन ने 5 अक्टूबर 2024 को डीयू के कुलसचिव व कॉलेज प्रिंसिपलों को सर्कुलर जारी कर ओबीसी विस्तार योजना के तहत स्वीकृत गैर शैक्षणिक पदों को भरने के लिए समय सीमा के विस्तार के संबंध में लिखा था कि उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों से कई अनुरोध प्राप्त हुए है। हालांकि इससे पहले भी यूजीसी सात बार ओबीसी एक्सटेंशन दे चुकी है लेकिन अधिकांश कॉलेजों ने इन पदों को नहीं भरा। ओबीसी एक्सपेंशन के इन पदों को भरने के लिए फोरम ने मांग की है कि यूजीसी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलसचिव व सभी प्रिंसिपलों को सर्कुलर जारी कर 31 मई 2025 तक इन पदों को भरने के लिए एक्सटेंशन दे। उन्होंने यह भी मांग की है कि इस बार कोई कॉलेज ओबीसी एक्सपेंशन के इन पदों को नहीं भरता है तो उनकी ग्रांट बंद कर देनी चाहिए।

फोरम के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन ने बताया है कि कॉलेज प्रिंसिपलों ने यह स्वीकार किया कि पिछले दो साल से शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया के चलते वे ओबीसी एक्सपेंशन के इन पदों को अभी तक नहीं भर पाए। प्रिंसिपलों का यह भी कहना है कि जब तक यूजीसी पुनः इन पदों को भरने संबंधी निर्देश नहीं देगी वे इन पदों को नहीं भर पाएंगे। इसलिए फोरम मांग करता है कि ओबीसी एक्सपेंशन स्कीम (ओबीसी विस्तार योजना) के अंतर्गत इन पदों को भरने के लिए पुनः एक साल का एक्सटेंशन देते हुए 31 मई 2025 तक समय दिया जाए। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के कुलसचिव व कॉलेज प्रिंसिपलों को सर्कुलर जारी किया जाए जिससे ओबीसी एक्सपेंशन के इन पदों को भरा जा सके। उन्होंने बताया है कि हर विभाग / कॉलेज में ओबीसी

एक्सपेंशन की सीटें खाली पड़ी हुई है लेकिन प्रिंसिपलों की मंशा इन्हें भरने की नहीं है क्योंकि इन पदों पर ओबीसी के उम्मीदवार सेक्शन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइब्रेरियन, एसपीएस, पीए, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट आदि पदों पर नियुक्ति होनी है परन्तु प्रिंसिपलों ने पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर लगाए हुए है।

डॉ. हंसराज सुमन ने बताया है कि गत वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की अवर सचिव वीना मैनन ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलसचिव व सभी महाविद्यालयों के प्रिंसिपलों को 5 अक्टूबर 2023 से हम कुल सात बार समय सीमा को आगे बढ़ाने का निर्देश दे चुके हैं। अब काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद समय सीमा के विस्तार के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों से प्रार्थना पत्र भेजे जा रहे हैं। यूजीसी ने यह भी जानकारी दी की ओबीसी एक्सपेंसन के पदों को भरने हेतु पुनः समय सीमा विस्तार के लिए शिक्षा मंत्रालय की संस्तुति के लिए इसे आगे भेज दिया गया है। फिलहाल कॉलेज के प्रिंसिपलों ने ओबीसी एक्सपेंशन के इन पदों का रोस्टर रजिस्टर तैयार किया हुआ, वे यूजीसी से सर्कुलर आने का इंतजार कर रहे हैं।

डॉ.सुमन ने बताया है कि यूजीसी इससे पहले भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलसचिव व कॉलेजों के प्रिंसिपलों को 17 मार्च 2021 व 26 अप्रैल 2022 को सर्कुलर जारी कर 31 मार्च 2023 तक ओबीसी एक्सपेंशन के इन पदों को स्पेशल ड्राइव के तहत भरने को कहा गया था किंतु प्रिंसिपलों ने इन पदों को भरने में कोई तत्परता नहीं दिखाई। हालांकि कुछ कॉलेज प्रिंसिपलों ने तो इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन तक नहीं निकाले थे, जिन कॉलेजों के प्रिंसिपलों ने इन पदों को भरने के विज्ञापन निकाले उन्होंने ट्रेंकेटिड गवर्निंग बॉडी का बहाना बनाकर इन पदों को नहीं भरा, जबकि पूर्व में ट्रेंकेटिड गवर्निंग बॉडी के माध्यम से स्थायी शिक्षकों व गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति होती रही है। उन्होंने बताया है कि ओबीसी एक्सपेंशन के इन पदों को भरने के लिए यूजीसी पहले भी सात बार एक्सटेंशन दे चुकी है बावजूद इसके इन पदों को नहीं भरा गया। डॉ. सुमन का कहना है कि जो कॉलेज ओबीसी एक्सपेंशन के पदों को नहीं भरते ऐसे कॉलेजों के प्रति यूजीसी को सख्त कार्यवाही करते हुए इनका अनुदान बंद कर देना चाहिए। उन्होंने यूजीसी से यह भी मांग की है जो कॉलेज ओबीसी एक्सपेंशन के पदों को नहीं भरते उन कॉलेजों से ओबीसी ग्रांट का पैसा ब्याज सहित लौटने को कहा जाए।

डॉ. सुमन ने बताया है कि ओबीसी एक्सपेंशन के सबसे ज्यादा पद दिल्ली सरकार के कॉलेजों में हैं। इन कॉलेजों के प्रिंसिपल गवर्निंग बॉडी का बहाना बनाकर पदों को भरने में रुचि नहीं ले रहे हैं जबकि पिछले दो साल से इन कॉलेजों में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, सिर्फ़ 9 मार्च 2024 को चुनाव आचार संहिता के कारण बंद किया गया है। डॉ. सुमन का कहना है कि जब दिल्ली सरकार के इन कॉलेजों में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति हो सकती है तो ओबीसी एक्सपेंशन के पदों की क्यों नहीं भरा जाता है ? डॉ. सुमन का कहना है कि होना तो यह चाहिए था कि यूजीसी द्वारा जारी 5 अक्टूबर 2023 के सर्कुलर को स्वीकार करते हुए कॉलेज प्रिंसिपलों को अपने यहाँ ओबीसी एक्सपेंशन के पदों को भरने संबंधी रोस्टर रजिस्टर तैयार कर पदों को विज्ञापित करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। डॉ. सुमन ने कॉलेजों के एक्टिंग व ऑफिसिएटिंग प्रिंसिपलों से यह भी मांग की है कि यूजीसी द्वारा ओबीसी कोटे के स्वीकृत पदों को भरने संबंधी जो दिशा निर्देश जारी किए थे वे कॉलेज अपने यहाँ ओबीसी पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द ट्रेंकेटिड गवर्निंग बॉडी से पास कराकर इन पदों के विज्ञापन निकालें। उनका यह भी कहना है कि जो कॉलेज ओबीसी विस्तार योजना के तहत इन पदों को ना भरें यूजीसी को उनकी ग्रांट रोक देनी चाहिए। क्योंकि ओबीसी विस्तार योजना के तहत इन्हें कई बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है।

डॉ. हंसराज 'सुमन'
चेयरमैन - फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस
फोन-9717114595

आप का भाजपा पर हमला, कहा- बीजेपी ने षडयंत्र कर केजरीवाल को भेजा जेल, जवाब देने के लिए तैयार

परिवहन विशेष न्यूज

पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार हैं। भाजपा ने दिल्ली सरकार को गिराने के लिए षडयंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, ताकि दिल्लीवालों को मिल रहीं सुविधाएं बंद हो जाएं।

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने रविवार सुबह 'जेल का जवाब वोट से' कैंपेन के तहत साइक्लोथॉन का नेतृत्व किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने 'जेल का जवाब वोट से' लिखी पीली टी-शर्ट पहनकर साइकिल रैली निकाली। मयूर विहार फेस दो से निकाली गई साइकिल रैली के दौरान लोगों से भाजपा की तानाशाही के खिलाफ वोट कर जेल का जवाब देने की अपील की गई।

मयूर विहार फेस दो पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के निर्वाचन क्षेत्र में आता है और यहां के लोगों का कुलदीप कुमार को भारी जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ महिलाओं को एक हजार रुपये महीना देने का इंतजाम किया। भाजपा ने दिल्ली सरकार को गिराने के लिए षडयंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, ताकि दिल्लीवालों को मिल रहीं सुविधाएं बंद हो जाएं। इसलिए भाजपा की इस साजिश का जवाब देने के लिए दिल्लीवाले तैयार हैं।

कुलदीप कुमर ने कहा कि हमने 'जेल का जवाब वोट से' कैंपेन के तहत मयूर विहार फेस दो के इस्कॉन मंदिर से साइक्लोथॉन का आयोजन किया। दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार है। किस तरह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और षडयंत्र करके उनको जेल में डाला गया। सुप्रीम

कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी। आज हम सब लोग भाजपा की साजिश का जवाब देने के लिए तैयार हैं।

कुलदीप कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं को एक हजार रुपये की सौगात देने का काम किया। इसलिए भाजपा ने षडयंत्र करके उनको जेल में डाला, ताकि आम आदमी पार्टी टूट जाए और दिल्ली की सरकार गिराई जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार दिल्ली की घेराबंदी कर रही है। लगातार दिल्ली की जनता को परेशान कर रही है। कभी अधिकारियों तो कभी एलजी के माध्यम से भाजपा दिल्ली की सरकार को गिराने का षडयंत्र कर रही है। भाजपा चाहती है कि केजरीवाल सरकार को गिराकर दिल्ली के लोगों को मिल रही बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं को बंद कर दिया जाए।

उन्होंने कहा कि भाजपा को हम बता देना चाहते हैं कि जब तक अरविंद केजरीवाल हैं, तब तक किसी में ताकत नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के काम को रोक सके। दिल्ली की जनता को मिल रही सुविधाओं को रोक सके। दिल्ली वालों के साथ उनके बेटे-भाई अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। इस बार दिल्ली की जनता ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल कर जेल का जवाब वोट से देने का काम करेगी।

इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो न्यायालय द्वारा क्या फैसला सुनाया जाना है इसका फैसला भी सरकार करेगी। बड़ा सवाल?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत प्राप्त करने के बाद केजरीवाल ने खुले मंच से साफ साफ शब्दों में जनता को संबोधित कर यह घोषणा कर दी है यदि 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो वह 5 जून को ही जेल से बाहर होंगे। क्या इसका अर्थ अब यह मान लिया जाय की इंडी गठबंधन के जीतने के बाद सरकार ही भारत देश के न्यायालय और आदेशों का संचालन करेंगी ? वैसे भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिन मुद्दों को आधार बनाकर केजरीवाल को बिना जमानत मांगे अंतरिम जमानत प्रदान की है उससे **भानुमती का पिटारा खुल गया** - भ्रष्टाचारियों की मौज, धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल के लिए दिए गए आदेश पर भरोसा करते और एक उदाहरण मानते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी पूर्व पंजाब मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को अंतरिम जमानत दे दी, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पीएमएलए के तहत

मामला दर्ज किया गया है, ताकि वह भी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें। सख्त पीएमएलए को कमजोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और मुख्य रूप से संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता जी को धन्यवाद,

वैसे देश का जागरूक नागरिक होने के नाते मन में प्रश्न जरूर उठने लगा है की अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गलत फैसले हो जाए तो उनके विरुद्ध कोई चर्चा, कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो सकती ? **आखिर भारत देश की जनता के साथ ऐसा क्यों ?**

आसमान से बरस रही आग : कल रहा सीजन का सबसे गर्म दिन, अब दो दिन के लिए रेड अलर्ट; ऐसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल

परिवहन विशेष न्यूज

कल दिल्ली का नजफगढ़ इलाका सबसे गर्म रहा। यहां का अधिकतम तापमान 47 .8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब दो दिन के लिए रेड अलर्ट है।

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में आसमान से आग बरस रही है। दिन के समय लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं जताई है। विभाग ने दिल्ली में अगले दो दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रविवार को दिल्ली का पारा 44 डिग्री को पार कर सामान्य से चार डिग्री अधिक दर्ज किया गया। यह सीजन का सबसे गर्म दिन रहा।

प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली के मुताबिक रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से चार डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह सामान्य से दो डिग्री अधिक है। दिल्ली का नजफगढ़ इलाका सबसे गर्म रहा। यहां का अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा मंगेशपुर और पीतमपुरा का तापमान भी 47 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। रविवार को आसमान साफ रहा। दिल्ली के अधिकांश स्थानों पर लू चली। जबकि कुछ स्थानों पर भीषण लू चली।

मौसम विभाग ने सोमवार को आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है। कई स्थानों पर लू की स्थिति रहेगी, जबकि कुछ स्थानों पर भीषण लू की स्थिति बन सकती है। दिन में तेज 25-35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हवाएं चल सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 21 मई तक रेड अलर्ट की स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद उत्तर-पश्चिम दिशाओं से चल रही हवाओं की दिशाओं में बदलाव हो सकता है जिससे कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि तापमान में ज्यादा सुधार नहीं होगा, लेकिन 24 मई से एक बार फिर तापमान बढ़ सकता है। आशंका है कि तापमान बढ़कर 45 डिग्री को पार कर जाएगा।

दो साल बाद मई में सबसे दिन

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिल्ली का पारा साल 2022 के बाद सबसे गर्म रहा। इससे पहले 16 मई 2022 को दिल्ली का तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग की माने तो मई माह में अभी 12 दिन शेष हैं। ऐसे में आशंका है कि इस बार मई माह में तापमान 47 डिग्री को छू सकता है। दिल्ली में रविवार को तीन इलाकों में पारा 47 से अधिक दर्ज किया गया है।

दिल्ली में बढ़ रहा पानी का संकट

तापमान बढ़ने के साथ दिल्ली में पानी का संकट बढ़ने लगा है। नजफगढ़, उत्तम नगर, संगम विहार सहित दूसरे क्षेत्रों में पानी सप्लाई प्रभावित हो रही हैं। वहीं टैंकर के लिए भी इलाकों में चार से पांच दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के टोल फ्री नंबर पर पानी के लिए मदद मांगने या टैंकर बुक करवाने की सुविधा भी नहीं चल रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार को टैंकर बुक करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800117118 पर कई बार कॉल किया गया, लेकिन पानी की सुविधा पर जाने के बाद फोन कट जाता था। उनका कहना है कि द्वारका में पानी के लिए सभी लोग परेशान हो रहे हैं। कई जगहों पर लोगों को पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है।

बिभव को बोलना पड़ेगा: इन सवालों के जवाब चाहती है दिल्ली पुलिस, गिरफ्तारी से पहले PA ने मिटा दिए सबूत!

जांच में सहयोग न करने की वजह से बिभव कुमार अपने आईफोन का पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं। फॉरेंसिक और साइबर एक्सपर्ट की मदद से डिलीट गए डाटा को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम आवास पर हुई मारपीट के मामले में पुलिस मुख्यमंत्री के निजी सचिव बिभव कुमार से पूछताछ कर उस दिन का सच जानने का प्रयास कर रही है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी का कहना है कि बिभव जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए 150 सवालों की सूची तैयार की है।

मामले की जांच कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गुरुवार को स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद अचानक बिभव गायब हो गए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दो दिन गायब रहने के दौरान उन्होंने जमकर सबूतों से छेड़छाड़ की है। छानबीन के दौरान पता चला है कि बिभव ने घटना के बाद मुंबई जाकर अपना आईफोन-15 फॉर्मेट कर दिया। रविवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम जांच के लिए मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची। कई लोगों से पूछताछ के बाद टीम ने सीएम आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर और एक प्रिंटर को अपने कब्जे में लिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि डीवीआर की जांच से पता चला कि मारपीट वाले समय की फुटेज डीवीआर से गायब है।

जांच में सहयोग न करने की वजह से बिभव कुमार अपने आईफोन का पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं। फॉरेंसिक और साइबर एक्सपर्ट की मदद से डिलीट गए डाटा को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस उस दिन मुख्यमंत्री आवास पर ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों की सूची तैयार कर रही है। उनसे भी जल्द पूछताछ की जाएगी।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एफआईआर दर्ज करने के बाद फौरन बिभव की तलाश शुरू कर दी गई थी। छानबीन की गई तो पता चला कि बिभव पंजाब में मौजूद हैं। एक टीम को फौरन पंजाब रवाना किया गया। टीम अभी पंजाब नहीं पहुंची थी कि पता चला कि वह पंजाब में नहीं मुंबई में मौजूद हैं। पंजाब वाली टीम को आधे रास्ते से वापस बुला लिया गया। बाद में टीम मुंबई पहुंच गई। इस बीच शनिवार सुबह लोकल इंटेलिजेंस से पुलिस

को पता चला कि बिभव मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं। जिले के स्पेशल स्टाफ को वहां भेजा गया। उस समय बिभव अपने कमरे में ही मौजूद थे। टीम को देखते ही वह खुद ही बाहर आ गया। गिरफ्तारी के समय आप सांसद राघव चड्ढा भी वहीं मौजूद थे।

वहीं से सीधे बिभव को कश्मीरी गेट थाने लाकर पूछताछ की गई। वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। शाम करीब 4.15 बजे उनको औपचारिक तौर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि छानबीन के लिए पुलिस की टीम बिभव को मुंबई भी लेकर जा सकती है। इस पर विचार किया जा रहा है।

सांसद से मारपीट के पीछे किसकी साजिश पता लगाएगी पुलिस...

मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए स्वाति के बयान, उनकी चोट और मेडिकल रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि सांसद के साथ बेरहमी से मारपीट करने के अलावा उनको घसीटा भी गया। क्या यह एकाएक आए गुस्से का नतीजा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। हालांकि बिभव पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस फिर भी सच से पर्दा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।

मामले की जांच कर रहे एक अधिकारी ने बताया कि पिछले करीब नौ सालों से बिभव कुमार मुख्यमंत्री के निजी सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। इस साल अप्रैल में उनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी थीं। इसके बाद भी वह अपने पद पर बने हुए थे। इसके पीछे कोई खास वजह थी। पुलिस उनसे पूछताछ कर इसका पता लगा रही है।

कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि बिभव कुमार दिल्ली से बाहर नहीं गए थे। उन्होंने अपना मोबाइल किसी के हाथ पंजाब और मुंबई भेजा। बाद में उसे मुंबई में फॉर्मेट करवा दिया गया। वह अपराध स्थल पर ही रुककर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते रहे। पुलिस इन सब तथ्यों से पर्दा उठाने का प्रयास कर रही है।

कुछ सवाल, जिनकी पुलिस लेगी जानकारी...

. वारदात वाले दिन स्वाति मालीवाल कितने बजे मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची।
. उनके आने के समय बिभव कुमार कहां पर मौजूद थे।
. उनको यह किसने बताया कि स्वाति सीएम से मिलने आई हैं।
. क्या स्वाति ने सीएम आवास पर आने के लिए कोई अपाइंमेंट लिया था।
. स्वाति मालीवाल कितने सालों से पार्टी से जुड़ी हुई हैं।
. क्या इससे पूर्व सीएम आवास पर आने पर स्वाति ने अपाइंमेंट लिया था।
. स्वाति मालीवाल के साथ उन्होंने मारपीट क्यों की।
. सीएम आवास पर सिक्योरिटी को किसने बुलाया।
. वारदात के समय सीएम हाउस में कौन-कौन लोग मौजूद थे।
. क्या घटना की जानकारी सीएम को दी गई थी।
. इस घटना के बाद वह कहां-कहां गए।
. वारदात के तीन दिन बाद उन्होंने शिकायत क्यों दी।
. मामला दर्ज होने के बाद उन्होंने अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट क्यों कर दिया।

'इन लोगों ने ऑपरेशन झाड़ू शुरू किया, ये आप को कुचलना चाहते हैं', केजरीवाल का बीजेपी पर वार

केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने ऑपरेशन झाड़ू शुरू किया है। ये आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश में हैं। हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आप का बैंक अकाउंट सीज किया जाएगा।

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दफ्तर में आप विधायक और पार्षद भी मौजूद रहे।

इस दौरान केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने ऑपरेशन झाड़ू शुरू किया है। ये आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश में हैं। हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आप का बैंक अकाउंट सीज किया जाएगा। इसके बाद हमारी पार्टी का ऑफिस खाली किया जाएगा।

केजीवाल ने कहा कि पिछले 2 साल से इन्होंने(भाजपा) हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इन्होंने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, कल मेरे PA तक को गिरफ्तार कर लिया। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि आप एक-एक करके गिरफ्तार कर रहे हैं, आज हम सब साथ ही आ रहे हैं आप गिरफ्तार कर लो, हम डरने वाले नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि यह पार्टी एक विचार है। नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन विचार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री एक नेता को गिरफ्तार करोगे, ऐसे में 100 नेता पैदा होंगे। केजरीवाल पर आरोप लगाते हैं वह भ्रष्टाचारी है, लेकिन जानता पूछ रही है शराब घोटाले का पैसा कहां है। लेकिन यहां कोई एक पैसा नहीं मिला। फर्जी केसों को बना रहे हैं। भाजपा ने कहा था कि केजरीवाल खलिस्तान बनाकर वहां का पीएम बनना चाहता है। यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप लोग स्तर्क रहना।

रेलवे स्टेशन पर बनेगा सिटी बस स्टैंड, हर रूट के लिए मिलेंगी ई-बसें

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद। आने वाले समय में गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। स्टेशन के सिटी साइड में बस स्टैंड बनाया जाएगा। इसके लिए 8,974 वर्ग मीटर जमीन पर रेलवे ने काम शुरू करा दिया है। यहां से शहर के हर रूट के लिए ई-बसें यात्रियों के लिए उपलब्ध होंगी। स्टेशन परिसर के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने की योजना है। 365 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम तेज हो गया है। सेक्शन इंजीनियर पीके पांडेय का कहना है कि पार्किंग की फाउंडेशन का काम करीब 50 फीसदी पूरा हो चुका है। पार्किंग स्थल पर एक साथ करीब 500 वाहन खड़े हो सकेंगे। पार्किंग स्थल पर ई-वाहनों के चार्जिंग की भी सुविधा रहेगी। स्टेशन से शहर के हर रूट पर चलने वाले ई-बसों का डिस्पले स्क्रीन पर होता रहेगा।

स्टेशन पर यात्रियों को नहीं सताएगी गर्मी और सर्दी, बनेगी ग्रीन बिल्डिंग

आधुनिक रेलवे स्टेशन के निर्माण में सीमेंट और ईंट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग बनेगी। यहां यात्रियों को गर्मी और सर्दी नहीं सताएगी। एसी ब्लॉक पर दीवारें बनाई जा रही हैं। इंजीनियरों का कहना है कि ईंट से एसी ब्लॉक का वजन कम होता है। इस तकनीक से बनने वाली बिल्डिंग का तापमान हमेशा सामान्य रहता है।

बेसमेंट में पार्किंग, ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेस्टोरेंट

बेसमेंट में पार्किंग और ऊपर की मंजिल पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट बनाने की योजना है। ट्रेन लेट होने पर यात्री यहां नाश्ता, भोजन और शॉपिंग कर सकेंगे। यात्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था यहां रहेगी। वीआईपी लाउंज, ट्रेन की लाइव लोकेशन के लिए डिस्पले लगे होंगे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर का यह दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन होगा।

एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए बनेगा वन-वे

एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशन पर यात्रियों के लिए वन-वे बनेगा। एक तरफ से यात्री प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और दूसरी तरफ से बाहर निकलेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन परिसर में 32 लिफ्ट और इतने ही एस्कलेटर लगाए जाने की योजना पर काम चल रहा है।

धोबीघाट की ओर बनेगा एक और एफओबी

सेक्शन इंजीनियर पीके पांडेय का कहना है कि धोबीघाट आरओबी के बाद यात्रियों के लिए एक एफओबी बनेगा। इससे यात्री प्लेटफॉर्म पर और बाहर जा सकेंगे। दिसंबर 2025 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

बिल्डिंग के नीचे बनेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट

विजयनगर साइड में बिल्डिंग के नीचे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। यहां पानी को रीसाइक्लिंग कर ट्रीट किया जाएगा। स्टेशन का पानी प्लांट में जाएगा और ट्रीट होकर वापस स्टेशन पर आएगा। जल सरंक्षण के लिए स्टेशन के दोनों ओर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा।

ये होंगे निर्माण

कर्मचारियों के लिए तीन टावरों में तीन बीएचके के 96 क्वार्टर
दो यूनिट टाइप फोर एक मंजिल
टाइप फाइव का एक यूनिट
पर्किंग के ऊपर सौर ऊर्जा प्लांट

दो सौ गाड़ियों का ठहराव

दिल्ली-हावड़ा रेलखंड पर बने इस स्टेशन से रोजाना करीब 400 ट्रेनें गुजरती हैं। वहीं, 200 ट्रेनों का ठहराव होता है। करीब 80 हजार यात्री रोजाना यहां से ट्रेन पकड़ते हैं। वहीं, त्योहारी सीजन में यात्रियों की संख्या एक लाख से ऊपर पहुंच जाती है।

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की स्थापना 1865-66 में हुई थी।

चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान; लगा जाम

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद के इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र में एनएच नौ पर रविवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे चलती कार में अचानक आग लग गई। धुआं निकलता देख चालक कार से नीचे उतर गया। सूचना पर पहुंचे अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तब तक कार जल चुकी थी। आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है।

गाजियाबाद। इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र में एनएच नौ पर रविवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे चलती कार में अचानक आग लग गई। धुआं निकलता देख चालक कार से नीचे उतर गया। सूचना पर पहुंचे अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तब तक कार जल चुकी थी। आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक, इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र में छिजारसी कट के पास एक कार दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जा रही थी।तभी अचानक आगे से धुआं निकलने लगा। आग की तेज लपटें निकलने लगी। चालक कार से नीचे उतर गया। आग पूरी कार में फैल गई।

आगजनी से कोई हताहत नहीं

सूचना पर अग्निशमनकर्मी मौके पर गाड़ी लेकर और आग बुझाने का काम शुरू किया। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई। आग से कोई हताहत नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश के इस जिले में गर्मियों की वजह से 25 मई तक कक्षा आठ तक स्कूल बंद

डीएम इन्द्र विक्रम सिंह ने जिले के कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों को 25 मई तक के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। गर्मी के बढ़ते तापमान को देखते हुए आदेश जारी करते हुए बताया कि हीट वेव का प्रकोप है। ऐसे में बच्चों के साथ समस्या आ सकती है। सभी विद्यालयों को 20 से 25 मई 2024 तक बंद करने के लिए आदेशित किया जाता है।

गाजियाबाद। डीएम इन्द्र विक्रम सिंह ने जिले के कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों को 25 मई तक के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने गर्मी के बढ़ते तापमान को देखते हुए आदेश जारी करते हुए बताया कि हीट वेव का प्रकोप है। ऐसे में बच्चों के साथ समस्या आ सकती है। इस कारण सभी विद्यालयों को 20 मई से 25 मई 2024 तक बंद करने के लिए आदेशित किया जाता है, जिसका सभी स्कूल प्रबंधन पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

गाजियाबाद में देर रात आभूषण कारोबारी की लूटी स्कूटी, अपनी बाइक छोड़कर फरार हुए बदमाश

कोतवाली क्षेत्र के चंद्रपुरी में रविवार देर रात आभूषण कारोबारी से बाइक सवार दो बदमाशों ने स्कूटी लूट ली। घटना के समय पीड़ति दुकान बंद कर घर जा रहे थे। मौके पर बदमाश अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। चंद्रपुरी निवासी पुनीत की चौपाल पर सीताराम ज्वेलर्स के नाम से प्रतिष्ठान है। रविवार देर रात करीब साढ़े दस बजे पुनीत अपनी दुकान बंद कर स्कूटी पर घर जा रहे थे।

गाजियाबाद। कोतवाली क्षेत्र के चंद्रपुरी में रविवार देर रात आभूषण कारोबारी से बाइक सवार दो बदमाशों ने स्कूटी लूट ली। घटना के समय पीड़ति दुकान बंद कर घर जा रहे थे। मौके पर बदमाश अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। चंद्रपुरी निवासी पुनीत की चौपाल पर सीताराम ज्वेलर्स के नाम से प्रतिष्ठान है। रविवार देर रात करीब साढ़े दस बजे पुनीत अपनी दुकान बंद कर स्कूटी पर घर जा रहे थे। चंद्रपुरी में घर के पास पहुंचने पर व्यापारी के एक बाइक पर आए दो युवकों है हाथ पर डंडा मार दिया। इससे व्यापारी का संतुलन बिगड़ गया और बदमाश उनको तमंचा दिखाकर स्कूटी लूटकर फरार हो गए। मौके पर आरोपित अपनी बाइक छोड़ गए।

यादगार होगी स्मृति ईरानी की जीत!

शिव शरण त्रिपाठी

कांग्रेस के रणनीतिकार भले ही अपनी रणनीति से संतुष्ट हो। भले ही गांधी परिवार अपनी साख बचाने की कोई भी दलील दे पर सच्चाई यही है कि राहुल गांधी ने अमेठी सीट से चुनाव लड़ना कतई उचित नहीं समझा।

कभी कांग्रेस की खानदानी सीट मानी जाने वाली अमेठी से 2019 में पहले भाजपा की स्मृति ईरानी से चुनाव हारना और अब 2024 में राहुल गांधी का पलायन करना निःसंदेह यह बताने को काफी है कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी से टक्कर लेने का साहस नहीं दिखा सके। अलवक्ता कांग्रेस ने राहुल गांधी की बजाय अर्से तक गांधी परिवार के अमेठी, रायबरेली में चुनाव प्रबन्धक एवं वफादार सिपहसालार रहे किशोरी लाल शर्मा को चुनाव मैदान में उतारकर प्रत्यक्षः यह जताने की कोशिश की हैं कि गांधी परिवार अमेठी से अपने पुराने रिश्ते को बरकरार रखना चाहता है।

कांग्रेस के रणनीतिकारों को उम्मीद थी कि चूंकि राहुल गांधी पड़ोस की गांधी परिवार की खानदानी सीट रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं सो किशोरी लाल शर्मा को इसका लाभ मिलना तय है। यही नहीं चूंकि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत रायबरेली व अमेठी सीट कांग्रेस के खाते में गई अतएवं दोनो ही सीटों पर गठबंधन की प्रमुख भागीदार सपा के वोटों का लाभ मिलना तय है।

कांग्रेस के रणनीतिकार भले ही अपनी रणनीति से संतुष्ट हो। भले ही गांधी परिवार अपनी साख बचाने की कोई भी दलील दे पर सच्चाई यही है कि राहुल गांधी ने अमेठी सीट से चुनाव लड़ना कतई उचित नहीं समझा। उन्हें परिवार की 2019 में अपनी हारी खानदानी सीट अमेठी से मम्मी श्रीमती सोनिया गांधी की जीती रायबरेली कहीं ज्यादा सुरक्षित लगी।

जहां तक अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी के मुकाबले में किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारने की बात है तो उनके उतारने से अमेठी में न तो कोई उत्साह की लहर है न तो उन्हे अमेठी हाथोहाथ लेने को तैयार है। समर्पित कांग्रेसजनों और पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के अलावा न तो कोई बड़ा कांग्रेसी नेता उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है और न ही उन्हे गांधी परिवार से कोई विशेष तरजीह दी जा रही है। यदि ऐसा न होता तो श्री शर्मा के नामांकन के मौके पर प्रियंका गांधी अवश्य मौजूद रहती। जबकि वह पड़ोस में यानी रायबरेली में अपने भाई राहुल के नामांकन के अवसर पर जोश-ओ-खरोश के साथ उपस्थित थी। यह मान लिया जाये कि भाई के नाते प्रियंका की प्राथमिकता राहुल गांधी थे तो भी प्रियका के रॉबर्ट वाड्रा तो उपस्थित रह ही सकते थे।

जहां तक इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल सपा व अन्य के कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन मिलने का सवाल है, हालात बता रहे हैं कि सपा समर्थक खासकर यादव समाज के लोगों का रूझान कांग्रेस प्रत्याशी की तुलना में भाजपा प्रत्याशी की ओर कहीं ज्यादा है।

जिस तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, स्मृति ईरानी के जुलूस से लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने के मौके पर उपस्थित रहे और उन्होने पड़ोस के सुल्तानपुर में अपनी सुसराल बताकर अपने को यहां का दामाद बताकर अपना हक जताया। उससे भी यादव विरादरी का अधिकाधिक वोट श्रीमती ईरानी को मिलना ही मिलना है।

यहां यह भी कम गौरतलब नहीं है कि अमेठी के जिन दो सीटों पर सपा विधायकों का कब्जा है उनमें से एक गौरीगंज के सपा विधायक सपा से लगभग प्रत्यक्ष भी न भी सही अप्रत्यक्ष रूप से नाता तोड़ चुके हैं। उनका पूरा परिवार हाल ही में भाजपा में शामिल हो चुका है।

ज्ञात रहे सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज सीट से लगातार तीन बार चुनाव जीतकर एक रिकार्ड बना चुके हैं। उनका इस सीट के मतदाताओं पर काफी अच्छा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में उनके समर्थकों का अधिकाधिक वोट कांग्रेस के श्री शर्मा की बजाय भाजपा की श्रीमती ईरानी को मिलना तय माना जा रहा है।

सपा की दूसरी विधान सभा सीट अमेठी पर भी ऐसा ही नजारा दिखने को मिल रहा है। यहां से सपा विधायिका महाराजी देवी का बेटा और बेटी सहित पूरा कुनबा ही श्रीमती ईरानी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में जुटा हुआ है। ज्ञातव्य है महाराजी देवी के पति गायत्री प्रजापति भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते एक अर्से से जेल में बंद है और उन्हे लगता है कि भाजपा की शरण में जाने से उनके पति व परिवार को राहत मिल सकती है।

महाराजी देवी प्रजापति ओबीसी से आती हैं और उनकी बिरादरी कुम्हारों के अलावा उनके खास समर्थक मानी जाने वाली जातियों मौर्य, नाई आदि का भी भरपूर समर्थन भाजपा प्रत्याशियों को मिलना तय माना जा रहा है।

जानकार सूत्रों का कहना है कि यहां पर यह भी कम काबिलेगौर नहीं है कि जब 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी को सपा-बसपा गठबंधन का पूरा समर्थन प्राप्त था तब भी भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी को ओबीसी के 70 फीसदी मतदाताओं का समर्थन हासिल हुआ था और कुर्मी तथा कौरी जाति का तो 80 फीसदी से अधिक समर्थन मिला था।

भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक और महत्वपूर्ण बात यह बतायी जा रही है और वो है बसपा का सपा से अलग होकर स्वतंत्र चुनाव लड़ना। समझा जा रहा है कि ओबीसी जाति के रवि प्रकाश मौर्य भाजपा व कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि यह तथ्य भी सामने आ रहा है कि बसपा के चलते मुस्लिम व दलित वोटों में बंटवारा तय है। जिसका खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा।

राम मंदिर बनने के बाद से दलित परिवारों का ज्यादा से ज्यादा समर्थन भाजपा को मिलना सुनिश्चित है। जहां तक मुस्लिम मतों का सवाल है कुछ हद तक मुस्लिम महिलाओं का वोट भी भाजपा प्रत्याशी के खाते में जा सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्मृति ईरानी के समर्थन में अब तक दो-दो बार रैलिया करने से उदासीन मतदाताओं में जोश देखने को मिल रहा है। उपरोक्त तमाम तथ्यों, हालातों के अलावा स्मृति ईरानी का अमेठी के लोगों के बीच रहकर उनके सुख दुख में शामिल होना और क्षेत्र के उतरोत्तर विकास के लिये हर संभव प्रयास करना उनकी जीत को और पुख्ता बनाता है।

अब तो यहां तक दावे किये जाने लगे हैं कि इस बार भाजपा प्रत्याशी स्मृति कम से कम दो लाख वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा को पराजित करने में सफल होगी।

10 मिनट तक बच्ची को नोचते रहे कुत्ते, शरीर पर आए 20 से अधिक घाव

गाजियाबाद। शनिवार दोपहर एसआर भट्ठे पर आवारा कुत्तों के झुंड के हमले से मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। 10 मिनट तक हमलावर कुत्तों ने बच्ची के शरीर पर 20 से अधिक घाव कर दिए। वह चीखती चिल्लाती रही लेकिन कुत्तों के भौंकने आवाज के आगे उसकी आवाज दब गई। कुत्तों के लगातार भौंकने पर भट्ठे पर काम रहे एक मजदूर ध्यान कुत्तों की ओर गसा। बच्ची को लहूलुहान देखकर वह शोर मचाते हुए फावड़ा लेकर मौके पर पहुंचा और जरीफ भी डंडा लेकर मौके पर पहुंचे और कुत्तों से बच्ची को बचाया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्ची के पैर से लेकर गर्दन तक हर जगह गहरे जख्म हो गए थे।

आनन-फानन में बच्ची को लेकर नजदीक के अस्पताल परिजन लेकर गए, यहां डाक्टरों ने बच्ची के गाजियाबाद के संजय नगर अस्पताल भेज दिया। यहां बच्ची को एंटी रेबीज की वैक्सीन लगाई गई और घाव पर पट्टी बांधकर दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में रेफर कर दिया जहां करीब चार बजे उसकी मौत हो गई। गहरे घाव बच्ची की मौत का कारण बन गए। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मचा है, मां रुखसाना का रो- रोकर बुरा हाल है। एसीपी नरेश कुमार का कहना है कि घटना की जानकारी किसी ने थाने पर नहीं दी, मामले की जांच कराई जाएगी।

भट्ठे से पांच सौ मीटर दूरी पर मंडाराते हैं आवारा कुत्ते

भट्ठे से करीब पांच सौ मीटर दूरी पर स्थित तालाब में मछली पालन होता है। जरीफ ने बताया कि कुत्तों के झुंड तालाब में मछली खाने के लिए आता है, तालाब पर आने वाले कुत्ते खूंखार किस्म के है।

18 दिल में कई लोगों को काट चुके कुत्ते

मोदीनगर व मुरादनगर में कई लोगों को कुत्ते काट कर घायल कर चुके है। एक सप्ताह पूर्व मोदीनगर में बेगमाबाद में घर के बाहर टहल रही महिला को कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया था।

मुरादनगर जलालाबाद पुर गांव में घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को कुत्ते ने काट कर घायल कर दिया। शनिवार शाम जलालपुर गांव निवासी इशिका(6)पुत्री ब्रजलाल अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी बीच आवारा कुत्ते ने उसके हाथ में काट लिया।

अवैध असलहा सप्लाई करने वाले चार अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

गाजियाबाद। बिहार और मध्य प्रदेश से पिस्टल व तमंचे लाकर दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई करने वाले चार अंतरराज्यीय तस्करों को क्राइम ब्रांच ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। इनमें एक तस्कर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई की हुई है जबकि दो तस्कर मुरादनगर थाने के हिस्ट्रीशीटर व जिलाबदर अपराधी हैं। पुलिस ने इनके पास से चार पिस्टल, चार मैगजीन, छह तमंचे और एक स्कूटी व एक बाइक बरामद की है।

एडीसीपी अपराध सच्चिदानंद ने बताया कि पकड़े गए तस्कर मुरादनगर निवासी अनस, मुरादनगर के रावली रोड निवासी अनस, टीला मोड़ के फर्रुखनगर निवासी आरिफ और नगर कोतवाली के डासना गेट निवासी इनाम हैं। अनस ने दिल्ली विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई की है।

पूछताछ में अनस ने बताया कि पढ़ाई के बाद उसकी मुलाकात मेरठ के अमन उर्फ अन्नू से हुई जो बिहार व मध्य प्रदेश से असलहों की सप्लाई करता था। उसके

साथ मिलकर उसने भी सप्लाई करना शुरू कर दिया। अनस 2021 में मुरादनगर में शाहरूख की हत्या के मामले में जेल गया था। जेल से छूटने के बाद उसकी मुलाकात अनस गाजी से हुई। इसके बाद दोनों मिलकर मेरठ के मोईन और अमन उर्फ अन्नू से पिस्टल व तमंचे लाकर ईनाम, आरिफ व अंकित को बेच देते हैं। एडीसीपी ने बताया कि फरार अंकित, मोईन और अमन उर्फ अन्नू की तलाश की जा रही है।

दोनों अनस हैं हिस्ट्रीशीटर और जिलाबदर

एडीसीपी ने बताया कि अनस ने 2021, इनाम से 2014 और अनस पहलवान 2016 में हत्या के मामले में जेल गए थे। वहीं आरिफ कुरैशी पर भी हत्या, हत्या के प्रयास समेत 18 मामले दर्ज हैं। अनस ने 2021 में मुरादनगर में शाहरुख नाम के युवक की हत्या की थी जिसमें मेरठ के अमन उर्फ अन्नू ने अवैध हथियार दिलवाए थे। दोनों अनस मुरादनगर थाने के ए श्रेणी के हिस्ट्रीशीटर हैं और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने तीन मई 2024 को छह माह के लिए जिलाबदर किया है।

50 हजार में पिस्टल पांच हजार में बेच रहे थे तमंचा

पूछताछ में तस्करों ने पुलिस को बताया कि वह बिहार और मध्य प्रदेश से पिस्टल 20 हजार रुपये लाते हैं, जिसे वह 40 से 50 हजार रुपये में बेच देते हैं। वहीं तमंचा भी 2200 रुपये में लाकर पांच हजार रुपये तक बेच रहे थे।

मारुति की हैचबैक कार स्विफ्ट को खरीदना है बेहतर या फिर बलेनो को घर लाने में होगी समझदारी, जानें पूरी डिटेल

देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता मारुति सुजुकी की ओर से हाल में ही नई Swift 2024 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है। कंपनी की ओर से पेश की गई इस हैचबैक कार को खरीदने में फायदा होगा या फिर प्रीमियम विकल्प के तौर पर ऑफर की जाने वाली Baleno एक बेहतर विकल्प साबित होगी। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी की ओर से 9 May 2024 को भारतीय बाजार में New Swift 2024 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। कंपनी की इस हैचबैक कार में कई बेहतरीन फीचर्स के साथ ही इंजन को बदला गया है। लेकिन कंपनी की प्रीमियम हैचबैक Baleno भी कई बेहतरीन फीचर्स के साथ उसी कीमत में आती है। दोनों में से किस कार में किस तरह के फीचर्स को दिया जाता है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

कितना दमदार इंजन

मारुति की ओर से स्विफ्ट की चौथी पीढ़ी में नया जेड सीरीज इंजन दिया गया है। जिसमें तीन सिलेंडर मिलते हैं। नए इंजन से इसे 60 किलोवाट की पावर मिलती है और 111.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 5स्पीड मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन को दिया जाता है। इस गाड़ी को एजीएस ट्रांसमिशन के साथ एक लीटर पेट्रोल में 25.75 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसके मैनुअल वेरिएंट से गाड़ी को 24.80 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। वहीं बलेनो में कंपनी पुराना के-सीरीज इंजन देती है। जिसे चार सिलेंडर के साथ ऑफर किया जाता है। जिससे बलेनो को 90 पीएस की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें भी 5स्पीड मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन मिलता है। इसके मैनुअल ट्रांसमिशन से 22.35 और एएमटी ट्रांसमिशन से 22.94 का एवरेज मिलता हे।

कैसे हैं फीचर्स

मारुति ने नई Swift में छह स्पीकर सेटअप, फ्रंट में ट्विटर, नौ इंच टचस्क्रीनऑल न्यू सस्पेंशन सिस्टम, वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, सुजुकी कनेक्ट, हाइड्रॉलिक क्लच, रियर एसी वेंट्स, रियर पैसेंजर्स को फोन चार्ज करने के लिए दो चार्जिंग पोर्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टेयरिंग पर ऑडियो कंट्रोल्स के अलावा क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स के साथ ही छह एयरबैग के साथ लाया गया है। इसके साथ ही इसमें सेफ्टी के लिए हिल होल्ड असिस्ट, ईएसपी, रिवर्स पार्किंग कैमरा, एबीएस, ईबीडी जैसे सेफ्टी फीचर्स को दिया गया है। वहीं बलेनो में भी एलईडी प्रोजेक्टर हैडलैंप, एलईडी डीआरएल, 16 इंच अलॉय व्हील्स, ड्यूल टोन डैशबोर्ड, ऑटो एसी, रियर एसी वेंट, स्टेयरिंग माउंटिड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, 9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, 360 डिग्री व्यू कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स को दिया जाता है।

कितनी है लंबाई-चौड़ाई

मारुति की स्विफ्ट को 3860 एमएम लंबा रखा गया है। इसकी चौड़ाई 1735 एमएम, ऊंचाई 1520 एमएम है। इसका व्हीलबेस 2450 एमएम और बूट स्पेस 265 लीटर का है। वहीं मारुति बलेनो में कंपनी की ओर से 3990 एमएम की लंबाई दी जाती है। इसकी चौड़ाई 1745 एमएम, ऊंचाई 1500 एमएम, व्हीलबेस 2520 एमएम और बूट स्पेस 318 लीटर का दिया जाता है।

कितनी है कीमत

मारुति की ओर से स्विफ्ट 2024 की एक्स शोरूम कीमत 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 9.65 लाख रुपये तक है। वहीं बलेनो की एक्स शोरूम कीमत की शुरूआत 6.66 लाख रुपये से हो जाती है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 9.88 लाख रुपये है।

निसान कर रही मैगनाइट के फेसलिफ्ट वर्जन को लाने की तैयारी, जानें क्या मिली जानकारी

जापानी वाहन निर्माता Nissan की ओर से भारतीय बाजार में एक ही एसयूवी Magnite को ऑफर किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से जल्द ही मौजूदा एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को लाने की तैयारी की जा रही है। कंपनी की ओर से किस तरह के बदलावों के साथ कब तक फेसलिफ्ट वर्जन को पेश किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में जापानी कार निर्माता Nissan की ओर से Magnite एसयूवी को ऑफर किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को ला सकती है। Nissan Magnite के Facelift वर्जन को कब तक लाया जा सकता है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Nissan Magnite Facelift आएगी

रिपोर्ट्स के मुताबिक निसान की ओर से मैग्नाइट के फेसलिफ्ट वर्जन को भारतीय बाजार में लाने की तैयारी की जा रही है। जिसमें एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर में कई बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन इसके इंजन में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना काफी कम होगी।

हो रही टेस्टिंग

बाजार में पेश करने से पहले कंपनी की ओर से इसकी टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग के दौरान इस एसयूवी को कई बार देखा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक फेसलिफ्ट वर्जन में नए बंपर, नए हेडलैंप और ग्रिल असेंबली के साथ ही अपडेटिड एलईडी लाइट्स और अलॉय व्हील्स को दिया जा सकता है। इंटीरियर में डैशबोर्ड में ज्यादा बदलाव नहीं होगा लेकिन, कुछ नए फीचर्स को भी ऑफर किया जा सकता है।

कितना दमदार होगा इंजन

रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से एसयूवी के इंजन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें मौजूदा एक लीटर के इंजन का विकल्प ही दिया जाएगा। जिससे एसयूवी को 72 हॉर्स पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इसके अलावा इसमें टर्बो इंजन का विकल्प भी मिलता रहेगा। जिससे एसयूवी को 100 हॉर्स पावर और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें पांच स्पीड मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन के विकल्प को भी दिया जाएगा।

कब होगी लॉन्च

कंपनी की ओर से अभी इस बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे साल के आखिर या 2025 की शुरूआत में लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च के समय इसकी कीमत में मामूली बढ़ोतरी भी की जा सकती है।

किनसे होगा मुकाबला

भारतीय बाजार में निसान की ओर से मैग्नाइट एसयूवी को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इसका बाजार में सीधा मुकाबला Renault Kiger, Tata Punch, Hyundai Exter, Maruti Brezza और Fronx, Hyundai Venue जैसी एसयूवी से होता है।

खरीदनी है कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की कार, जानें किस गाड़ी पर है मई 2024 में कितनी वेटिंग

भारतीय बाजार में Compact SUV सेगमेंट के वाहनों को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ऐसे में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मारुति टाटा से लेकर हुंडई और किआ तक अपने बेहतरीन उत्पादों को ऑफर करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किस कंपनी की किस एसयूवी को May 2024 में खरीदने पर कितना इंतजार करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। Compact SUV सेगमेंट में कंपनियों की ओर से कई बेहतरीन विकल्पों को भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सेगमेंट में आने वाली किस गाड़ी पर May 2024 में कितनी वेटिंग चल रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Tata Nexon पर कितनी वेटिंग

रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा की ओर से इस सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली Nexon पर कम से कम एक महीने की वेटिंग चल रही है। पुणे, गुरूग्राम, कोलकाता, फरीदाबाद, इंदौर जैसे शहरों में इस एसयूवी पर सबसे कम इंतजार करना पड़ रहा है। इसके अलावा नोएडा, पटना, कोयबंटूर, गाजियाबाद, चंडीगढ़, सूरत, लखनऊ जैसे शहरों में इस एसयूवी पर करीब दो से ढाई महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है।

Maruti Brezza के लिए कितना इंतजार

मारुति की ओर से इस सेगमेंट में ब्रेजा को ऑफर किया जाता है। कंपनी की इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को अगर मई महीने में बुक करवाया जाता है, तो इसकी डिलीवरी के लिए कम से कम एक महीना और ज्यादा से ज्यादा तीन महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, गाजियाबाद में इसपर सबसे कम वेटिंग है।

Hyundai Venue पर भी है वेटिंग

साउथ कोरियाई वाहन निर्माता हुंडई की ओर से भी वेन्यू को इस सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। कंपनी की एसयूवी को इस महीने में खरीदने पर कम से कम दो महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक मुंबई, हैदराबाद, चंडीगढ़ और फरीदाबाद में इस पर सबसे कम वेटिंग चल रही है।

Kia Sonet पर भी करना होगा इंजतार

किआ की ओर से सोनेट एसयूवी पर भी May 2024 में इंतजार करना पड़ रहा है। कंपनी की ओर से ऑफर की जाने वाली इस एसयूवी पर कम से कम एक महीने और अधिकतम तीन महीने की वेटिंग चल रही है। मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत, गाजियाबाद जैसे शहरों में इस पर सबसे कम वेटिंग है।

Nissan Magnite पर कम है वेटिंग

निसान की ओर से मैग्नाइट एसयूवी को ऑफर किया जाता है। जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी पर सबसे कम वेटिंग चल रही है। दिल्ली में इसे बिना इंतजार किए घर लाया जा सकता है। वहीं मुंबई, पुणे, गुरूग्राम, लखनऊ, सूरत, गाजियाबाद में 15 दिन से लेकर एक महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है।

शोरूम से लें जानकारी

अगर आप भी इस महीने में अपने लिए कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की किसी गाड़ी को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो सबसे पहले नजदीकी शोरूम पर जाकर जानकारी ली जा सकती है। सभी वाहनों पर मॉडल, शहर और शोरूम के मुताबिक वेटिंग पीरियड अलग-अलग भी हो सकता है।

एआरएआई ने पहली बार किया इलेक्ट्रिक स्कूटर का क्रैश टेस्ट, जानें डिटेल

भारत में लगातार इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों को सुरक्षित बनाने पर काम किया जा रहा है। ऐसे में देश की एक प्रमुख संस्था ARAI की ओर से पहली बार Electric Scooters की सुरक्षा की जांच के लिए Crash Test किया गया है। भारत में किस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को सुरक्षित बनाने पर काम किया जा रहा है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में Electric Scooters को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन इस तकनीक वाले स्कूटर्स में होने वाले हादसों के कारण भी इनकी सुरक्षा पर समय समय पर सवाल उठते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एआरएआई संस्थान की ओर से पहली बार Electric Scooters की क्रैश टेसटिंग की गई है।

ARAI ने की टेस्टिंग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से महाराष्ट्र के पुणे में Electric Scooters की टेस्टिंग की गई है। संस्थान की ओर से अपने प्लांट में तीन क्रैश टेस्ट की एक सीरीज को पूरा कर लिया है।

गुप्त रखी जानकारी

एआरएआई की ओर से क्रैश टेस्ट के दौरान डेटा का कैप्चर करने के लिए एक्सेलेरोमीटर और हाई स्पीड कैमरे का उपयोग किया गया। लेकिन संस्थान की ओर से जिन कंपनियों के वाहनों का क्रैश टेस्ट में उपयोग किया गया, उनकी जानकारी को गुप्त रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ट के दौरान कठोर अवरोधक का भी उपयोग किया गया था।

हो सकता है अनिवार्य

जिस तरह भारत एनसीएपी और ग्लोबल एनसीएपी जैसी संस्थाएं कारों की सुरक्षा के लिए क्रैश टेस्ट करती हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों के लिए क्रैश टेस्ट को अनिवार्य किया जा सकता है। जिससे सुरक्षा मानकों को बेहतर किया जा सकेगा।

किसे होगा नुकसान

रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर भारत में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों के लिए क्रैश टेस्ट को अनिवार्य किया जाता है, तो इससे उन कंपनियों को झटका लगेगा, जो अपने उत्पादों में तय मानकों की जगह सस्ती और खराब बैटरी, मोटर और अन्य पार्ट्स का उपयोग करती हैं।

किसे होगा फायदा

अगर देश में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों के क्रैश टेस्ट को अनिवार्य किया जाता है, तो इसका सीधा फायदा ग्राहकों को होगा। क्योंकि क्रैश टेस्ट के दौरान इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों को कई तरह से टेस्ट किया जाएगा, जिससे उनकी मोटर, बैटरी, चेसिस आदि की जांच हो पाएगी। इसका फायदा यह होगा कि बाजार में जो भी विकल्प ऑफर किए जाएंगे वह सुरक्षा के मामले में काफी बेहतर होंगे और उनमें आग लगने, खराबी आने जैसी घटनाएं काफी कम हो जाएंगी।

रॉयल इन्फील्ड गुरैल्ला 450 जल्द देगी मार्केट में दस्तक, लॉन्च से पहले सामने आ चुके हैं कई फीचर्स

हाल ही में इस बाइक की जो स्पाई तस्वीरें सामने आई हैं उनसे पता चलता है कि बाइक का प्रोडक्शन अब लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। नई तस्वीरों से संकेत मिलता है कि गुरिल्ला 450 में कई नए फीचर्स को जोड़ा जाएगा। बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस देने के लिए इसमें कई बड़े बदलाव किए जाने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। रॉयल एनफील्ड इन दिनों अपनी कई नई मोटरसाइकिलों को लेकर चर्चा में है। कंपनी इन दिनों भारतीय मार्केट के लिए Royal Enfield Guerrilla 450 पर काम कर रही है। इस बाइक को लॉन्च से पहले कई बार परीक्षण के दौरान स्पॉट किया जा चुका है। अब एक बार फिर इसके लेटेस्ट स्पाई शॉट्स सामने आए हैं, जिनसे आगामी बाइक का लुक पूरी तरह से देखने को मिलता है।

इस बाइक को कंपनी Himalayan 450 के लॉन्च के बाद लेकर आ रही है। यह शेरपा 450 इंजन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुई थी। उम्मीद है कि अपकमिंग Guerrilla 450 में यही प्लेटफॉर्म बरकरार रखा जाएगा।

परीक्षण के दौरान दिखी बाइक

हाल ही में इस बाइक की जो स्पाई तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे पता चलता है कि बाइक का प्रोडक्शन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। नई तस्वीरों से संकेत मिलता है कि गुरिल्ला 450 में कई नए फीचर्स को जोड़ा जाएगा। बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस देने के लिए इसमें कई बड़े बदलाव किए जाने की उम्मीद है। जो बाइक में टेस्टिंग के दौरान दिखी है भले ही उस पर कवर लगे हुए हैं। लेकिन, मुख्य फ्रेम और सबफ्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और बड़े पैमाने पर हिमालयन 450 के स्ट्रक्चर की ओर इशारा करते हैं।

क्या मिलेंगे फीचर्स

फॉर्ग्ड स्टील साइड स्टैंड भी इसमें दिखाई नहीं देता है। बाइक में गैटर और रोडस्टर-स्टाइल हैंडलबार के साथ आरएसयू टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स दिखाई देते हैं, जो इसकी स्ट्रीट पहचान को बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें सिंगल पीस सीट और अलॉय व्हील भी देखे गए हैं। इसमें हिमालयन से अलग फ्यूल टैंक दिया जाएगा। इसमें डुअल चैनल एबीएस के साथ डिस्क ब्रेक दिए जाएंगे। रेडिएटर ग्रिल शुरुआती प्रोटोटाइप से अलग दिखती है।

इंजन

इसमें Sherpa 450 इंजन मिलेगा, यह रॉयल एनफील्ड का पहला इंजन है जिसमें DOHC 4V हेड और लिक्विड कूलिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यह इंजन 40 पीएस और 40 एनएम का टॉर्क प्रदान करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स, स्लिपर क्लच और राइड-बाय-वायर थ्रॉटल के साथ जोड़ा गया है। बाइक की कीमत 2.5 लाख रुपये होने की उम्मीद है।

क्या वित्त मंत्री भैंसों पर भी 'विरासत कर' लगाएंगी

पी. चिदम्बरम

चल रहे लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा बहस किस मुद्दे पर हो रही है? एक तरफ नरेंद्र मोदी और कुछ सहयोगी हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी और शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य-विशिष्ट कमांडरों द्वारा संचालित बहु-आयामी चुनौती है।

चल रहे लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा बहस किस मुद्दे पर हो रही है? एक तरफ नरेंद्र मोदी और कुछ सहयोगी हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी और शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य-विशिष्ट कमांडरों द्वारा संचालित बहु-आयामी चुनौती है। चुनौती देने वालों में से प्रत्येक ने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं जिनमें बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, सांप्रदायिक विभाजन, असमानता, कानूनों का हथियारीकरण और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, महिलाओं के खिलाफ अपराध, भारतीय क्षेत्र पर चीनी सैनिकों का कब्जा, धन के हस्तांतरण में भेदभाव और मीडिया की अधीनता शामिल है। मोदी ने इन मुद्दों को ध्यान भटकाने वाला कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने बड़ी चतुराई से उन्हें किनारे कर दिया।

संयुक्त विपक्ष को मिस्टर जसप्रीत बुमराह की तरह क्लीन बोल्ड कर दिया और वास्तव में प्रेरित विचार भैंसों पर विरासत कर के साथ कथा स्थापित की। मुझे संदेह है कि यह विचार 'संपूर्ण राजनीति विज्ञान' में वर्षों के शोध से पैदा हुआ था। इस सवाल पर देशव्यापी पशुवत क्षमा करें, एनिमेटेड-बहस चल रही है, ''क्या केंद्रीय वित्त मंत्री भैंसों पर विरासत कर लगाएंगी?'' आइए बहस को समृद्ध करने का प्रयास करें।

जानवरों पर कर : मूल प्रश्न यह उठेगा कि क्या केंद्र सरकार द्वारा इस तरह का कर लगाना संवैधानिक होगा? 7वीं अनुसूची की सूची ढ्ढ की प्रविष्टि 58 में लिखा है, 'जानवरों और नावों पर कर' प्रथम दृष्टया, जानवरों पर कर लगाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास आरक्षित है। इसके विपरीत, केंद्र सरकार सूची ढ्ढ की प्रविष्टि 86, 87 या 88 के तहत कर को उचित ठहरा सकती है जो क्रमशः संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर, संपत्ति शुल्क और संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में कत्र्तव्यों से संबंधित है। कानूनी शब्दावली में, क्या भैंस हमेशा एक जानवर है या, जब वह 'विरासत में' मिलती है या 'उत्तराधिकार' से गुजरती है, तो क्या भैंस एक संपत्ति बन जाती है? इस प्रश्न के लिए सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के संदर्भ और संविधान पीठ द्वारा निर्णय की आवश्यकता हो सकती है। वरिष्ठ वकील की पशु आत्माएं पूरी तरह सक्रिय होंगी।

कर आधार : विचार के लेखक ने कहा, 'यदि आपके पास दो भैंस हैं, तो एक ले ली जाएगी' जिसका अर्थ है कि विरासत कर केवल दो या अधिक भैंसों पर लगाया जाएगा और कर की दर 50 प्रतिशत हो सकती है। मुझे डर है कि कर का प्रबंधन करना आसान नहीं है। यदि दो भैंसें हैं, तो किस भैंस पर कर लगेगा और कर संग्रहकत्र्ता उसे छीन लेगा? यदि दोनों एक ही लिंग और एक ही रंग की हैं, तो वह किसी एक को चुन सकते हैं, जब तक कि वह बुरिडन के गधे (पढ़ें:भैंस) के सामने आने वाली दुविधा में फंस न जाए और थकावट से मर न जाए। हालांकि, 2 भैंसों में से, यदि एक 'वह' है और दूसरी 'वह' है, तो वह किसे चुनेगी? इसके अलावा, भैंसें कम से कम 4 रंगों में आती हैं - भूरा, काला, सफेद और काला-भूरा। मान लीजिए कि 2 भैंसें काली और सफेद हैं, तो कर संग्रहकत्र्ता किसे चुनेगा? लैंगिक पूर्वाग्रह या नस्लीय पूर्वाग्रह के आरोप से बचने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नियम बनाने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, यदि संपत्ति में विषम संख्या में भैंसें हैं तो एक अजीब समस्या उत्पन्न होगी। कर संग्रहकत्र्ता 50 प्रतिशत की दर कैसे लागू करेगा और भैंस वध के आरोप से कैसे बचेगा?

कर की दर : लेखक ने 50 प्रतिशत की कर दर का प्रस्ताव रखा। क्या कानून को चुनौती नहीं दी जाएगी क्योंकि दर, प्रथम दृष्टया, जब्ती है? यदि कॉर्पोरेट कर की वर्तमान दरें (15, 22 या 30 प्रतिशत) या व्यक्तिगत आयकर दरें (42.8 प्रतिशत तक) लागू की जाती हैं, तो लेखक द्वारा कल्पना की गई एक साफ और सुरुचिपूर्ण कर गब्बर सिंह की तरह एक जटिल कर बन जाएगी। टैक्स (जी.एस.टी.) और भैंस टैक्स का सर्वत्र तिरस्कार किया जाएगा। अकेले दर पर बहस में संसद में कई दिन लग सकते हैं।

चार्जिंग अनुभाग : चार्जिंग अनुभाग कर कानून का सार है। ड्राफ्ट्समैन को उपयुक्त शब्दों के चयन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अंततः सी.बी.डी.टी. को एक भैंस-प्रधान दृष्टिकोण अपनाना होगा, विभिन्न आपत्तियों को संक्षेप में खारिज करना होगा और इस संभावना के प्रति पूरी तरह सचेत होकर एक पाठ पर निर्णय लेना होगा कि चार्जिंग अनुभाग को विभिन्न आधारों पर न्यायालयों में चुनौती दी जाएगी।

अनोखा टैक्स? : लेखक ने भैंसों पर 50 प्रतिशत की एक समान दर से एक अद्वितीय कर के रूप में विरासत कर पर विचार किया। सबसे निश्चित रूप से, उन्होंने मृतक की सभी संपत्तियों पर विरासत कर का प्रस्ताव नहीं किया। संभवतः, उसने सोचा कि भैंस एक विशेष उपचार की हकदार है। भारतीय पौराणिक कथाओं में मृत्यु के देवता यम, भैंसे पर सवार होकर आते हैं। यदि यम के दिव्य वाहन को नश्वर मनुष्यों द्वारा आविष्कार किए गए कार या बाइक या साइकिल जैसे वाहनों के साथ जोड़ा जाता है तो यह अपवित्रता होगी। यदि कर-लोलुप सी.बी.डी.टी. वित्त मंत्री को मृतक की सभी संपत्तियों पर विरासत कर लगाने के लिए मनाने में सफल हो गया, तो भैंस को अन्य कर योग्य संपत्तियों के साथ जोड़ दिया जाएगा और भैंसों पर विरासत कर एक 'प्रगतिशील' कर बन सकता है।

भैंस भविष्य है : नरेंद्र मोदी सार्वजनिक वित्त, विशेषकर कराधान के सिद्धांतों के गहन ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक क्रांतिकारी कर का प्रस्ताव रखा है जो भविष्य के कर नवाचारों का मार्ग प्रशस्त करेगा। नकदी-भैंस का दूध निकालने के लिए, केंद्र सरकार भैंस-पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर सकती है और 806,000 करोड़ रुपए (भारत के प्रति जिले 1000 करोड़ रुपए की दर से) का प्रारंभिक परिव्यय प्रदान कर सकती है। नर भैंसे खेती के लिए मशीनीकृत हलों की जगह ले सकते हैं, जिससे डीजल की बचत होगी। भैंस की खाद हानिकारक रासायनिक उर्वरकों की जगह ले सकती है। भैंस का दूध भारत में पसंदीदा दूध बन सकता है। मैं लेखक के विकसित भारत के दृष्टिकोण को सलाम करता हूं। अन्य देशों को पछाड़ते हुए, भारत में 2 राष्ट्रीय पशु होंगे-जंगल में शानदार बाघ और मानव बस्तियों में बहुउद्देशीय भैंस।

संपादक की कलम से

क्या अमरीका प्रवासी असंतुष्टों की हत्या को लेकर भारत को ब्लैकमेल कर रहा?

संयुक्त राज्य अमरीका और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने भारत पर प्रवासी असंतुष्टों को निशाना बनाकर हत्या की नीति चलाने का आरोप लगाने के लिए एक मीडिया अभियान तेज कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि ऐसी कोई नीति नहीं है। फिर भी, अमरीकी बाइडेन प्रशासन के साथ-साथ कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया उन दावों पर जवाबदेही की मांग कर रहे हैं कि नई दिल्ली पश्चिमी राज्यों में रहने वाले भारतीय असंतुष्टों की जासूसी, उत्पीडऩ और हत्या के 'अंतर्राष्ट्रीय दमन' में संलग्न है।

आरोपों ने राजनीतिक संबंधों को गंभीर रूप से कलंकित कर दिया है। सबसे बड़ा झगड़ालु उदाहरण कनाडा है। पिछले साल कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा सार्वजनिक रूप से भारतीय स्टेट एजैंटों पर एक भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद, नई दिल्ली ने दर्जनों कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था।इस महीने रिश्ते तब और तनावपूर्ण हो गए जब 'वाशिंगटन पोस्ट' ने एक लंबा लेख प्रकाशित किया जिसमें दावा किया गया कि भारतीय सुरक्षा सेवाएं अमरीकी और कनाडाई नागरिकों की हत्याएं आयोजित कर रही थीं। पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के अंदरुनी घेरे में उच्च स्तरीय भारतीय खुफिया प्रमुखों का नाम दिया गया है। निहितार्थ यह है कि राजनीतिक हत्याओं की नीति को भारत सरकार के शीर्ष स्तर पर मंजूरी दी गई है।

कथित हत्या कार्यक्रम का लक्ष्य सिख प्रवासी समुदाय के सदस्य हैं। अमरीका, कनाडा और ब्रिटेन में सिखों की बड़ी प्रवासी आबादी है। हाल के वर्षों में, सिखों के बीच अपनी मातृभूमि पंजाब को भारत से अलग करने के लिए नए सिरे से अभियान चलाया गया है। नई दिल्ली सरकार खालिस्तान नामक एक नए राज्य के अलगाववादियों के आह्वान को भारतीय क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा मानती है। मोदी सरकार ने सिख अलगाववादियों को आतंकवादी करार दिया है। भारतीय अधिकारियों ने दशकों से उत्तरी भारत के पंजाब क्षेत्र में राजनीतिक हत्या सहित सिखों का दमन किया है। कई सिख सुरक्षा के लिए और एक अलग राष्ट्र के लिए अपना आंदोलन जारी रखने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों में भाग गए। मोदी सरकार ने पश्चिमी राज्यों पर 'सिख आतंकवादियों' को बढ़ावा देने और भारतीय संप्रभुता को कमजोर करने का आरोप लगाया है।

पिछले जून में, वैंकूवर के एक उपनगर में एक प्रमुख सिख नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो एक पेशेवर हिट-शैली की घटना प्रतीत होती थी। हरदीप सिंह निज्जर की एक धार्मिक स्थल के बाहर 3 हमलावरों ने हत्या कर दी थी। भारतीय स्टेट मीडिया ने उसे आतंकवादी बताया, लेकिन निज्जर के परिवार ने आतंकवाद में उसकी किसी भी संलिप्तता से इंकार किया। उनका दावा है कि उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने पंजाबी अलगाववाद को बढ़ावा दिया था।

वहीं, 'द पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, अमरीकी अधिकारियों ने एक जाने-माने अमरीकी-सिख नागरिक के खिलाफ हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया, जो कनाडाई पीड़ित का सहयोगी था। दोनों व्यक्ति उत्तरी भारत के पंजाब क्षेत्र में खालिस्तान के एक नए स्वतंत्र देश की स्थापना के लिए उत्तरी अमरीका में सिख प्रवासियों के बीच एक अनौपचारिक जनमत संग्रह कराने के प्रयासों का समन्वय कर रहे थे। 'द पोस्ट' लेख में सिख नेताओं के खिलाफ हत्या की साजिश रचने के लिए भारत की राज्य जासूसी एजैंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के एक अधिकारी विक्रम यादव का नाम लिया गया है।

चिंतन

पंजाब में होने वाले संसदीय चुनाव : वादे और हकीकत

जैसे -जैसे पंजाब में संसदीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों का भाग्य अधर में लटक गया है। पंजाब, अपनी 13 संसदीय सीटों के साथ एक महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान है। खासकर अमृतसर सीट राज्य की सबसे अहम सीटों में से एक है।

जैसे -जैसे पंजाब में संसदीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों का भाग्य अधर में लटक गया है। पंजाब, अपनी 13 संसदीय सीटों के साथ एक महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान है। खासकर अमृतसर सीट राज्य की सबसे अहम सीटों में से एक है। इस बार ज्यादातर प्रमुख राजनीतिक दलों ने बिना कोई गठबंधन बनाए अकेले चुनाव लडऩे का फैसला किया है। हर प्रत्याशी मतदाताओं से तरह-तरह के वादे कर रहा है। हालांकि, इनमें से कई वादे पार्टी लाइन से हटकर आश्चर्यजनक रूप से समान हैं। आम प्रतिज्ञाओं में नशीली दवाओं के मुद्दे को खत्म करना, युवाओं को रोजगार प्रदान करना, इंदौर के मानकों के अनुरूप अमृतसर का विकास करना, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार फिर से शुरू करना और पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार करना शामिल है।

दिलचस्प बात यह है कि किसी भी उम्मीदवार ने अभी तक श्री हरमंदिर साहिब, जिसे सोने की परत चढ़े होने के कारण स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, के लिए परेशानी मुक्त रास्ता प्रदान करने का वादा नहीं किया है। अनुमान है कि शहर में प्रतिदिन 1,00,000 से अधिक पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद केंद्र सरकार ने गलियारा परियोजना के नाम से श्री हरमंदिर साहिब के आसपास सौंदर्यीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की। यह परियोजना 2016 में शिरोमणि अकाली दल (बादल) और भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान हैरिटेज स्ट्रीट के निर्माण में परिणत हुई। हालांकि, हैरिटेज स्ट्रीट तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को अभी भी चारदीवारी वाले शहर की संकीर्ण गलियों से गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद, अमृतसर में किसी भी उम्मीदवार ने श्री हरमंदिर साहिब तक आसान और परेशानी मुक्त मार्ग प्रदान करने का वादा नहीं किया है। इस समस्या को कम करने के लिए घी मंडी से और शेरां वाला गेट से एक मार्ग प्रस्तावित किया जा सकता है।

सभी उम्मीदवार स्थानीय लोगों से वादा कर रहे हैं कि वे अटारी-वाघा भूमि मार्ग के माध्यम से भारत-पाकिस्तान व्यापार को फिर से खोल देंगे। गौरतलब है कि 2018 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से आयातित सभी सामानों पर 200 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगा दी थी और पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन (एम.एफ.एन.) का दर्जा रद्द कर दिया था। जवाब में, पाकिस्तान ने 9 अगस्त, 2019 को पूर्ण व्यापार प्रतिबंध लगा दिया। भारत का कहना है कि 'आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते।' प्रश्न उठता है कि ये राजनेता द्विपक्षीय

संबंधों को फिर से शुरू किए बिना पाकिस्तान के साथ व्यापार को फिर से खोलने का वादा कैसे कर सकते हैं। अमृतसर में किसी भी उम्मीदवार ने बुनियादी सुविधाओं से वंचित सीमावर्ती निवासियों का मुद्दा नहीं उठाया है। हालांकि, ये राजनेता सीमावर्ती किसानों से वादा कर रहे हैं कि वे रैडक्लिफ लाइन तक कंटीली तार का विस्तार करेंगे, ताकि जिन किसानों के पास बाड़ के पार जमीन है, वे बिना किसी परेशानी और प्रतिबंध के अपनी जमीन जोत सकें।

गौरतलब है कि रैडक्लिफ लाइन पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए आपसी समझौते के मुताबिक, कोई भी देश वास्तविक अंतरराष्ट्रीय सीमा के 500 मीटर के भीतर कुछ भी निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए, इस मुद्दे का समाधान तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि दोनों प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता फिर से शुरू न हो जाए। इससे यह सवाल उठता है कि क्या उम्मीदवार अज्ञानी हैं या केवल वोट हासिल करने के लिए लोगों से झूठे वादे कर रहे हैं।

नशा उन्मूलन और युवाओं को रोजगार : पंजाब में सबसे गंभीर मुद्दों में से एक, बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं की समस्या है। प्रत्येक उम्मीदवार ने इस मुद्दे से डटकर निपटने की कसम खाई है। पंजाब वर्षों से नशीली दवाओं के गंभीर संकट से जूझ रहा है, जिसमें कई युवा नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। उम्मीदवारों ने मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने और नशे की लत के शिकार लोगों के लिए पुनर्वास प्रदान करने के लिए कड़े कदम उठाने का वादा किया है। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का भी वादा किया है, जिसका लक्ष्य उन्हें नशीली दवाओं से दूर रखना और उत्पादक गतिविधियों में संलग्न करना है। हालांकि, जमीनी हकीकत बेहद सख्त है। पिछली सरकारें भी इसी तरह के वादे कर चुकी हैं लेकिन नशीली दवाओं की समस्या जस की तस बनी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के अनुसार, पंजाब में भारत में नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों की दर सबसे अधिक है। इन वादों की प्रभावशीलता देखी जानी बाकी है, खासकर तब, जब उम्मीदवारों ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदमों की रूपरेखा नहीं बनाई। कई उम्मीदवार अपनी स्वच्छता के लिए मशहूर इंदौर को मॉडल शहर बता रहे हैं और अमृतसर को भी इसी तरह बदलने का वादा कर रहे हैं। यह मुझे राजनीतिक दलों के पिछले वादों की याद दिलाता है- एक ने अमृतसर को दिल्ली मॉडल जैसा बनाने का वादा किया था और दूसरे ने दावा किया था कि वह सड़कों को एक विशेष बॉलीवुड अभिनेत्री के गालों जितनी चिकनी बना देंगे। हालांकि, सत्ता में आने के बाद किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया गया। प्रत्येक शहर का अपना विशिष्ट चरित्र होता है, इसलिए नीति निर्माताओं को अमृतसर के लिए विशेष रूप से एक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। इसमें सीवेज सुविधाओं को बढ़ाने, पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे व्यवहार्य विकास कार्य शामिल होने चाहिएं।

सीमावर्ती निवासी और किसान : सीमावर्ती निवासियों और किसानों से किए गए वादे भी चुनाव अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। सीमावर्ती निवासियों को अक्सर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें बुनियादी सुविधाओं तक सीमित पहुंच और निरंतर सुरक्षा खतरे शामिल हैं। विशेष रूप से किसानों को कांटेदार तार की बाड़ से परे उनकी भूमि तक आसान पहुंच का वादा किया गया है। हालांकि, भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी समझौता अंतरराष्ट्रीय सीमा के 500 मीटर के भीतर किसी भी निर्माण पर रोक लगाता है, जिससे द्विपक्षीय वार्ता के बिना इन वादों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है।

निष्कर्ष : जैसे-जैसे संसदीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पंजाब में उम्मीदवारों द्वारा किए गए वादे आशा और संदेह के मिश्रण को दर्शाते हैं। हालांकि नशीली दवाओं के उन्मूलन, युवाओं को रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं लेकिन इन वादों की व्यावहारिकता संदिग्ध बनी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे भू-राजनीतिक तनाव ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है, खासकर व्यापार और सीमा मुद्दों के संबंध में। पंजाब में मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा किए गए वादों का गंभीरता से मूल्यांकन और उनके प्रस्तावों की व्यावहारिकता पर विचार करना चाहिए। असली परीक्षा इस बात में है कि क्या ये उम्मीदवार अपने वादे पूरे कर पाते हैं और राज्य में बेहद जरूरी बदलाव ला पाते हैं या नहीं। जैसे-जैसे चुनाव अभियान जारी है, लोगों के सामने आने वाले वास्तविक मुद्दों को संबोधित करने और पंजाब की बेहतरी के लिए स्थायी समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए।-रविंदर सिंह रोबिन

लाहौर की 'हीरा मंडी' और संजय लीला भंसाली

नरेंद्र मोदी और संजय लीला भंसाली में कुछ समानता है। वे दोनों पाकिस्तान को विकृत चश्मे से देखते हैं। पाकिस्तान के बारे में मोदी की धारणा एक ऐसे पड़ोसी देश की है, जिस पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, जो हमले के लिए भारतीय स्थानों की तलाश में हैं।

नरेंद्र मोदी और संजय लीला भंसाली में कुछ समानता है। वे दोनों पाकिस्तान को विकृत चश्मे से देखते हैं।

पाकिस्तान के बारे में मोदी की धारणा एक ऐसे पड़ोसी देश की है, जिस पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, जो हमले के लिए भारतीय स्थानों की तलाश में हैं। भंसाली शानदार झूठ रचने के लिए अपने कैमरे के लैंस का उपयोग करता है। उनकी नवीनतम लाहौर के रैड-लाइट एरिया, जिसे हीरा मंडी के नाम से जाना जाता है, पर 8 भाग की नैटफ्लिक्स श्रृंखला है। (संयोग से, इसका नाम महाराजा रणजीत सिंह के पसंदीदा राजा हीरा सिंह के नाम पर पड़ा।)

भंसाली एक अदम्य प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता, लेखक और संगीतकार-अपने आलोचकों के निशाने पर हैं। उन्होंने शेक्सपियर के रोमांस रोमियो और जूलियट के पवित्र रूपांतरण जैसी फिल्मों के साथ उन्हें चुनौती दी है इसे 'रामलीला' शीर्षक दिया। इसने कुछ रुढ़िवादी रामभक्तों को क्रोधित कर दिया। उन्हें इसका नाम बदलकर 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके विरोधियों ने उन्हें पहले दिल्ली उच्च न्यायालय और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ की शरण में जाने के लिए मजबूर किया, जिसने फिल्म की रिलीज के एक हफ्ते बाद उत्तर प्रदेश में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। इन बाधाओं के बावजूद, 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई।

भंसाली की अगली परियोजना 'बाजीराव मस्तानी' (2015) में मराठा नायक पेशवा बाजीराव प्रथम और उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी के बीच प्रेम का गुणगान किया गया। बाजीराव और मस्तानी के वंशजों ने यह दावा करते हुए उस फिल्म को अस्वीकार कर दिया कि 'भंसाली द्वारा अत्यधिक रचनात्मक स्वतंत्रता के कारण उनके पूर्वजों का गलत चित्रण हुआ।' जब स्थगन के लिए बाम्बे उच्च न्यायालय से संपर्क किया गया तो चतुराई से इंकार कर दिया गया। एक बार फिर, भंसाली ने अपने आलोचकों को जवाब दिया जब यह फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। भंसाली की 'पद्मावत' (2018) ने 13वीं सदी के मेवाड़ के राजपूत शासक रावल रतन सिंह और दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी को गुमनामी से बाहर निकाला। दोनों में खूबसूरत रानी पद्मिनी (उर्फ पद्मावत) के लिए प्रतिस्पर्धा थी। एक उग्र समापन में, भंसाली ने पद्मिनी को सामूहिक जौहर (आत्मदाह) करने के लिए चित्तौड़गढ़ किले के भीतर फंसी राजपूत महिलाओं की एक भीड़ का नेतृत्व करने के लिए कहा।

उपद्रवियों ने चिता शांत होने या भंसाली द्वारा अपनी फिल्म पूरी करने का इंतजार नहीं किया। 2017 में जयपुर में इसकी शूटिंग के दौरान, श्री राजपूत करणी सेना के दिग्गजों ने भंसाली, उनकी टीम के साथ मारपीट की और सैट को नुकसान पहुंचाया। बाद में, दूसरे समूह ने एक स्टूडियो और उस दौर की महंगी पोशाकें जला दीं। जब 'पद्मावत' साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई तो भंसाली ने बदला लिया।

भंसाली का नवीनतम प्रोडक्शन 'हीरामंडी : द डायमंड बाजार' उनके निजी दिमाग की उपज है। उन्होंने 14 वर्षों तक इस विचार को प्रस्तुत किया, फिर इसका निर्देशन किया, पटकथा का सह-लेखन किया, इसका संगीत तैयार किया और टैलीविजन के लिए एक लघु-श्रृंखला के रूप में इसका निर्माण किया। कहानी 1940 के दशक के अंत में लाहौर की हीरा मंडी पर आधारित है। यह तवायफों या नर्तकियों की कठिनाइयों से संबंधित है क्योंकि वे पहले सामाजिक स्वीकृति और फिर राजनीतिक स्वीकृति के लिए संघर्ष करती हैं। देर से देशभक्ति के विस्फोट में, वे लाहौर की सड़कों पर मार्च करती हैं, उनके घुंघरू सीढ़ियों पर झंकारते हैं, और अपने पूर्व ब्रिटिश ग्राहकों से आजादी की मांग करते हैं। जाहिर तौर पर, भंसाली चाहते थे कि फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार अभिनय करें। राजनीति में

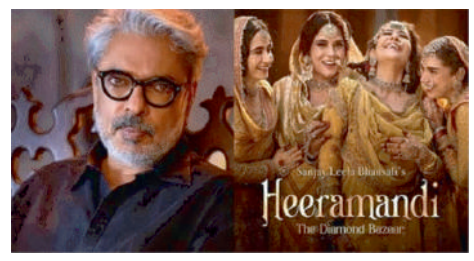

हस्तक्षेप किया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी अभिनेता भंसाली के आलोचकों द्वारा लगाए गए पहले आरोप के खिलाफ ढाल प्रदान कर सकते थे। इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता की कमी थी।

कई लाहौरी और वे बाहरी लोग जो इसे पसंद करते हैं, भंसाली की हीरा मंडी की सामाजिक स्थलाकृति को नहीं पहचानेंगे। उनके बहुभाषी कलाकार अपने उर्दू संवादों को तो अच्छी तरह दोहराते हैं लेकिन उचित उच्चारण की बारीकियों को नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी अनेक नायिकाएं भव्य रूप से सजी-धजी रहती हैं। उनके मांसल पुरुष अभिनेता अक्सर कपड़े उतारते थे; और केवल निचले स्तर के लोग-नौकरानियां और एक सिख प्रेमी-प्रेमिका-पंजाबी बोलते हैं। उनके नर्तक चक्करदार दरवेशों की तरह घूमते हैं, जो पहले के मुस्लिम सामाजिक नाटकों, विशेष रूप से 'मुगल-ए-आजम' और 'पाकीजा' में अपनी बड़ी बहनों की नकल करते हैं। उनके लोग अनावश्यक रूप से रोएंदार टोपी पहनते हैं जिसे एक बार दिवंगत अभिनेता/तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.जी. रामाचंद्रन ने लोकप्रिय बना दिया था।

इन वर्षों में, लाहौर की हीरा मंडी, अपने निवासियों की तरह अपना आकर्षण खोने लगी। व्यापार लाहौर के पुराने शहर से नए स्थानों पर स्थानांतरित हो गया जिससे लाहौर की फूड स्ट्रीट को रास्ता मिल गया। जो कोठे कभी घुंघरुओं की आवाज से गूंजते थे वहां अब महंगे रेस्तरां हैं। 1970 के दशक के बाद लंदन के सोहो में भी इसी तरह का बदलाव आया। कुछ पाठकों को याद होगा कि 1959 में, यू.के. ने सड़क अपराध अधिनियम लागू किया था। इसने सार्वजनिक स्थान पर घूमना-फिरना अपराध बना दिया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शहरों को आयातित सड़क पर चलने वालों से साफ करना था। हास्य अभिनेता पीटर उस्तीनोव ने इसकी उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि सड़कों की सफाई करना भोजन के बाद मेज को साफ करने जैसा है 'किसी को क्रॉकरी कहीं रखनी होगी' ।पिछले कुछ वर्षों में, लाहौर की हीरा मंडी से क्रॉकरी समृद्ध वातावरण में स्थानांतरित हो गई है। यदि वह हीरा मंडी अस्तित्व में है, तो यह भंसाली के टैक्नीकलर दिमाग के एक काल्पनिक रैड लाइट उपनगर के रूप में है।

-फकीर ऐजाजुद्दीन

जनवरी-मार्च में नायरा एनर्जी की पेट्रोल बिक्री 48 प्रतिशत बढ़ी, निर्यात घटा

परिवहन विशेष न्यूज

देश की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी ईंधन खुदरा कंपनी नायरा एनर्जी ने 2024 की पहली तिमाही में पेट्रोल की बिक्री में 48 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है। वहीं इस दौरान कंपनी के निर्यात में गिरावट आई है। तिमाही के दौरान कंपनी ने विशेष रूप से ईंधन की स्थानीय मांग को पूरा करने का प्रयास किया है। नायरा एनर्जी के शेयर अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हैं।

नई दिल्ली। देश की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी ईंधन खुदरा कंपनी नायरा एनर्जी ने 2024 के कैलेंडर साल की पहली तिमाही में पेट्रोल की बिक्री में 48 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है। वहीं इस दौरान कंपनी के निर्यात में गिरावट आई है। तिमाही के दौरान कंपनी ने विशेष रूप से ईंधन की स्थानीय मांग को पूरा करने का प्रयास किया है।

70 प्रतिशत स्थानीय बाजार में बेचा

कंपनी ने कहा कि जनवरी-मार्च तिमाही में उसने अपनी गुजरात की वाडिनार तेल रिफाइनरी में उत्पादित सभी पेट्रोलियम उत्पादों का 70 प्रतिशत स्थानीय बाजार में बेचा। बयान में कहा गया है कि नायरा एनर्जी ने मुख्य रूप से देश में बढ़ती पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया।

कंपनी ने कहा कि 'भारत में, भारत के लिए' के अपने संदेश से प्रेरित होकर उसने सालाना आधार पर घरेलू खुदरा बिक्री में 24 प्रतिशत और संस्थागत बिक्री में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

नायरा के पास 6,500 पेट्रोल पंप

पहली तिमाही में स्थानीय स्तर पर पेट्रोल की बिक्री बढ़कर 8.9 लाख टन हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में छह लाख टन रही थी। इस दौरान कंपनी की डीजल बिक्री 17 लाख टन पर स्थिर रही। देशभर में नायरा एनर्जी के 6,500 से अधिक पेट्रोल पंप हैं। यह निजी क्षेत्र की किसी कंपनी का सबसे बड़ा खुदरा नेटवर्क है।

शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं नायरा

नायरा एनर्जी लिमिटेड को पहले एस्सार ऑयल के नाम से जाना जाता था। यह ऑयल रिफाइनरी, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल बिजनेस में लगी हुई है। हालांकि, 2016 तक इसकी वित्तीय स्थिति काफी खराब हो गई थी। इसे रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने 12.9 अरब डॉलर में खरीद लिया। उसके बाद नायरा एनर्जी को शेयर मार्केट से डीलिस्ट करा लिया गया। उस वक्त इसकी प्राइस 262.80 रुपये प्रति शेयर थी।

इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले चेक कर लें अपना एआईएस, गलती हुई तो ठीक करने का मिलेगा मौका

आईटीआर से जुड़े ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने एआईएस को देखा जा सकता है। अब एआईएस में दिखाए गए विवरण पर रियल टाइम फीडबैक भी दे सकेंगे। वह फीडबैक उसी समय उस सोर्स के पास चला जाएगा जहां से इनकम टैक्स विभाग ने वह जानकारी ली है। फिर उस सोर्स ने क्या जवाब दिया है इसकी जानकारी भी आयकरदाता को मिल जाएगी।

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने से पहले अपना वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) जरूर चेक कर लें। उस विवरण में कोई गलती है तो इनकम टैक्स विभाग को अपना फीडबैक भी दे ताकि उस गलती को विभाग सुधार सके। अभी एआईएस में रियल टाइम फीडबैक देने की सुविधा नहीं है। पहली बार इनकम टैक्स विभाग की तरफ से यह सुविधा शुरू की गई है। एआईएस में साल भर के दौरान किए गए वैसे सभी वित्तीय लेन-देन का पूरा विवरण होता है जिस पर टैक्स लिया जा सकता है।

ई-फाइलिंग पोर्टल पर देख सकते हैं AIS

आईटीआर से जुड़े ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने एआईएस को देखा जा सकता है। अब एआईएस में दिखाए गए विवरण पर रियल टाइम फीडबैक भी दे सकेंगे। वह फीडबैक उसी समय उस सोर्स के पास चला जाएगा जहां से इनकम टैक्स विभाग ने वह जानकारी ली है। फिर उस सोर्स ने क्या जवाब दिया है, इसकी जानकारी भी आयकरदाता को मिल जाएगी।

जानकारी में बदलाव की जरूरत है तो एआईएस में संशोधन कर दिया जाएगा। टैक्स विशेषज्ञों ने बताया कि नौकरी करने वाला एक आदमी म्युचुअल फंड, शेयर बाजार, एलआईसी जैसी कई जगहों पर निवेश करता है और खरीद-फरोख्त करता है। म्युचुअल फंड कंपनी, शेयर बाजार जैसे माध्यम इनकम टैक्स विभाग को हमारी खरीद-फरोख्त की जानकारी देते हैं। लेकिन इसमें गलती भी हो सकती है।

मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 60,000 रुपए मूल्य के शेयर बेचे, लेकिन एआईएस में यह दिखा रहा है कि उसने एक लाख रुपए के शेयर बेचा है। इस जानकारी पर वह अपना फीडबैक देगा जो शेयर कंपनी के पास चला जाएगा और अगर वह कंपनी यह फीडबैक देता है कि हां, उस व्यक्ति ने एक लाख रुपए का नहीं, 60,000 रुपए मूल्य का शेयर बेचा है तो इनकम टैक्स विभाग एआईएस में संशोधन कर देगा। अगर वह इस फीडबैक को अस्वीकार कर देता है तो एआईएस में कोई बदलाव नहीं होगा।

चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) और टैक्स एक्सपर्ट एम.के. गुप्ता ने बताया कि इसका फायदा यह होगा कि लोग बिल्कुल सही आईटीआर भर सकेंगे। अभी अगर एआईएस में गलत सूचना भी होती है तो लोग उसे सही मानकर टैक्स भर देते हैं। इस सुविधा से पारदर्शिता बढ़ेगी और अनुपालन आसान हो जाएगा। एआईएस के विवरण पर फीडबैक देने के बाद सोर्स की तरफ दी गई प्रतिक्रिया की तारीख तक की जानकारी आयकरदाता को मिलेगी।

भारतीय शेयर मार्केट में बिकवाली, चीन के बाजार में निवेश; क्या चल है विदेशी निवेशकों के मन में?

आम चुनाव के नतीजों को लेकर अनिश्चितता और चीन के बाजारों में आकर्षक मूल्यांकन के चलते विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने मई में अब तक भारतीय शेयर बाजारों से 28242 करोड़ रुपये की निकासी की है। मॉरीशस के साथ भारत की कर संधि में बदलाव और अमेरिका में बांड प्रतिफल बढ़ने की चिंता के बीच अप्रैल में एफपीआई ने शेयरों से शुद्ध रूप से 8700 करोड़ रुपये निकाले थे।

नई दिल्ली। आम चुनाव के नतीजों को लेकर अनिश्चितता और चीन के बाजारों में आकर्षक मूल्यांकन के चलते विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने मई में अब तक भारतीय शेयर बाजारों से 28,242 करोड़ रुपये की निकासी की है। मॉरीशस के साथ भारत की कर संधि में बदलाव और अमेरिका में बांड प्रतिफल बढ़ने की चिंता के बीच अप्रैल में एफपीआई ने शेयरों से शुद्ध रूप से 8,700 करोड़ रुपये निकाले थे।

इससे पहले एफपीआई ने मार्च में शेयरों में 35,098 करोड़ रुपये और फरवरी में 1,539 करोड़ रुपये डाले थे। आगे चलकर चुनाव नतीजों के बाद एफपीआई के इक्विटी प्रवाह में नाटकीय बदलाव देखने को मिल सकता है। आंकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन अवधि में एफपीआई ने ऋण या बांड बाजार में 178 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

26,000 करोड़ निकाल चुके हैं FPI

इससे पहले एफपीआई ने मार्च में बॉन्ड बाजार में 13,602 करोड़ रुपये, फरवरी में 22,419 करोड़ रुपये और जनवरी में 19,836 करोड़ रुपये का निवेश किया था। कुल मिलाकर इस साल अब तक एफपीआई शेयरों से 26,000 करोड़ रुपये निकाल चुके हैं। हालांकि, इस दौरान उन्होंने बांड बाजार में 45,000 करोड़ रुपये डाले हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार का कहना है कि राजनीतिक स्थिरता की स्थिति में भारतीय बाजार में भारी निवेश आएगा।

चुनाव, हाई वैल्यूएशन से बिकवाली

वहीं, मोजोपीएमएस में मुख्य निवेश अधिकारी सुनील दमानिया ने कहा, 'चालू वित्त वर्ष में एफपीआई की बिकवाली की मुख्य दो वजह हैं। पहली चुनावी नतीजों को लेकर अनिश्चितता है। इसके अलावा बाजार मूल्यांकन काफी ऊंचा है जिसकी वजह से एफपीआई बिकवाली कर रहे हैं।'

सरकार ने निर्यातकों के लिए माफी योजना से 852 करोड़ रुपये जुटाए, अभी और बढ़ सकते हैं आंकड़े

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में भारत का व्यापारिक निर्यात 1 प्रतिशत बढ़कर 34.99 अरब डॉलर हो गया। वहीं इस महीने के दौरान व्यापार घाटा चार महीने के उच्चतम स्तर 19.1 अरब डॉलर तक बढ़ गया। गोल्ड इंपोर्ट बढ़ने से समीक्षाधीन महीने में आयात भी 10.25 प्रतिशत बढ़कर 54.09 अरब डॉलर हो गया जो अप्रैल 2023 में 49.06 अरब डॉलर था।

नई दिल्ली। सरकार ने निर्यातकों के लिए माफी योजना के तहत करीब 852 करोड़ रुपये जुटाए हैं। अग्रिम और ईपीसीजी की अनुमति वाले निर्यातकों से निर्यात प्रतिबद्धता में चूक के मामले में एकबारगी निपटान योजना शुरू की गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी इनका पूरा ब्योरा जुटाने की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने सीमा शुल्क और ब्याज के भुगतान की आखिरी तारीख 31 मार्च तय की है।

अधिकारी ने कहा, 'योजना के तहत 6,705 आवेदन दाखिल किए गए थे।' इस बीच, कई छोटे निर्यातकों ने सरकार से निर्यात प्रतिबद्धता में चूक के मामले में एकबारगी निपटान योजना को सितंबर तक जारी रखने का अनुरोध किया है। लुधियाना स्थित हैंड टूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने कहा है कि कई छोटे निर्यातक 45 दिन के भीतर एमएसएमई को भुगतान करने के अपने दायित्वों को पूरा करने के कारण योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में भारत का व्यापारिक निर्यात 1 प्रतिशत बढ़कर 34.99 अरब डॉलर हो गया। वहीं, इस महीने के दौरान व्यापार घाटा चार महीने के उच्चतम स्तर 19.1 अरब डॉलर तक बढ़ गया। गोल्ड इंपोर्ट बढ़ने से समीक्षाधीन महीने में आयात भी 10.25 प्रतिशत बढ़कर 54.09 अरब डॉलर हो गया, जो अप्रैल 2023 में 49.06 अरब डॉलर था।

सरकार की रविवाद से विश्वासरहित पहल विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाती है। सरकार ने निर्यात दायित्वों पर डिफॉल्ट की समस्या को कम करने के लिए एफटीपी 2023 के तहत विशेष एकमुश्त माफी योजना शुरू की है। इसका मकसद उन निर्यातकों को राहत देना है, जो लंबित मामलों से जुड़े उच्च शुल्क और ब्याज लागत के बोझ से दबे हुए हैं।

पिता लगाते थे आम का ठेला, बेटे ने खड़ी कर दी 400 करोड़ की कंपनी; जानिए 'आइसक्रीम मैन' की कहानी

आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर उद्योगपति रघुनंदन कामत (Raghunandan Kamath) का निधन हो गया। 75 साल के रघुनंदन लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने शनिवार को अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। रघुनंदन ने नेचुरल्स आइसक्रीम की नींव रखी थी। कंपनी ने उनके इंतकाल की सूचना सोशल मीडिया पर देते हुए लिखा कि नेचुरल्स फैमिली उन्हें हमेशा अपनी यादों में जिंदा रखेगी।

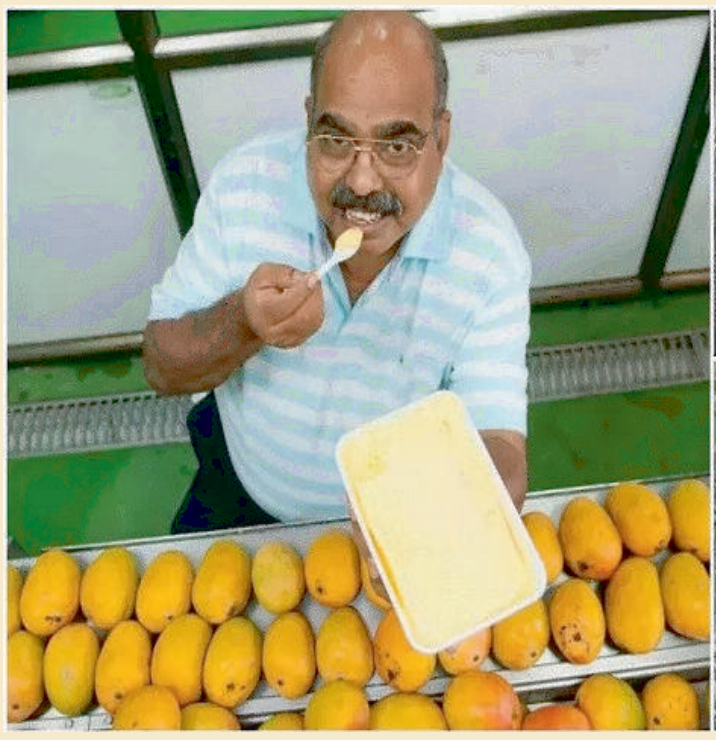

नई दिल्ली। आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर उद्योगपति रघुनंदन कामत (Raghunandan Kamath) का निधन हो गया। 75 साल के रघुनंदन लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने शनिवार को अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। रघुनंदन ने नेचुरल्स आइसक्रीम (Naturals Ice Cream) की नींव रखी थी। कंपनी ने उनके इंतकाल की सूचना सोशल मीडिया पर देते हुए लिखा कि नेचुरल्स फैमिली उन्हें हमेशा अपनी यादों में जिंदा रखेगी।

फल बेचने वाले घर में पैदा हुए थे रघुनंदन

रघुनंदन कामत का जन्म कर्नाटक के एक छोटे से शहर मुल्की में हुआ था। उनके पिता की आम का ठेला लगाते थे। रघुनंदन ने काफी कम उम्र से अपने पिता के काम में मदद करना शुरू कर दिया था। स्कूल में फेल होने के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वह सिर्फ 14 साल की उम्र में मुल्की छोड़कर अपने भाई के पास मुंबई चले गए और वहां भाई के साथ रेस्टोरेंट में काम करने लगे। बाद में रघुनंदन ने अपना रास्ता अलग कर लिया।

कैसे शुरू किया आइसक्रीम का बिजनेस?

रघुनंदन ने अपने आइसक्रीम बिजनेस की शुरुआत बड़े छोटे स्तर पर की। उन्होंने फरवरी 1984 में सिर्फ चार कर्मचारियों के साथ अपना कारोबार चलाया। उनके ग्राहकों को लुभाने का तरीका भी अनोखा था। वह आइसक्रीम के साथ पाव भाजी भी बेचा करते। इससे जो ग्राहक सिर्फ पाव भाजी खाने के इरादे से आते, वे तीखा लगने के बाद आइसक्रीम भी खाकर जाते।

रघुनंदन की आइसक्रीम भी लाजवाब होती। वह सिर्फ फल, दूध और चीनी से आइसक्रीम बनाते। उसमें कोई मिलावट नहीं होती। इससे लोगों का उन पर भरोसा बढ़ा और फिर लोग सिर्फ आइसक्रीम खाने के लिए ही उनके पास आने लगे। रघुनंदन ने अपने पिता से सही फलों का चुनाव करना और उन्हें सरंक्षित रखने का तरीका भी सिखा था, जिसका उन्हें आइसक्रीम बिजनेस में फायदा मिला।

400 करोड़ की कंपनी है नेचुरल्स आइसक्रीम

जब रघुनंदन का आइसक्रीम का बिजनेस चल निकला, तो उन्होंने पाव भाजी का काम बंद दिया। अब उनका पूरा फोकस सिर्फ नेचुरल्स आइसक्रीम पर था। उन्होंने मुंबई के जुहू में अपना पहला आइसक्रीम स्टोर खोला। आज इनकी संख्या 135 से अधिक है और ये देश के अलग-अलग हिस्सों में हैं। नेचुरल्स आइसक्रीम अब करीब 400 करोड़ रुपये की कंपनी है।

महंगा हवाई किराया भारतीय यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती, जानिए कब तक मिल सकती है राहत

पिछले कुछ साल में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में भारी उछाल आया है। लेकिन डिमांड के हिसाब से फ्लाइट उपलब्ध नहीं हैं जिसके चलते हवाई किराया काफी अधिक है। पिछले एक साल में 238 फीसदी का रिटर्न देने वाली ट्रैवल एजेंसी थॉकम कुक इंडिया के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन माधवन मेनन ने इस बात पर चिंता जताई है।

नई दिल्ली। पिछले कुछ साल में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में भारी उछाल आया है। लेकिन, डिमांड के हिसाब से फ्लाइट उपलब्ध नहीं हैं, जिसके चलते हवाई किराया काफी अधिक है। ट्रैवल एजेंसी थॉकम कुक इंडिया के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन माधवन मेनन का कहना है कि हवाई किराया अधिक होने से हॉलिडे या फिर बिजनेस के सिलसिले में सफर करने वाले यात्री प्रभावित हो रहे हैं। थॉकम कुक इंडिया के शेयरों ने पिछले एक साल में 238 फीसदी का रिटर्न दिया है।

मेनन ने समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में कहा कि शेड्यूल्ड फ्लाइट की संख्या बढ़ी है, लेकिन यह अभी भी डिमांड की तुलना में काफी कम है। उनका मानना है कि एयरलाइंस को अपनी कैपेसिटी तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। मेनन ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि नेटवर्क में नए विमान आने से डिमांड-सप्लाई की समस्या कम होगी, लेकिन इसके लिए काफी इंतजार करना होगा।'

भारतीयों को पसंद है वीजा फ्री एंट्री

मेनन थॉमस कुक इंडिया की भारत में विस्तार योजनाओं और चुनौतियों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने फिजिकल नेटवर्क बढ़ाने पर फोकस कर रही है। मेनन ने इस बात पर जोर दिया कि ई-वीजा, वीजा-ऑन-अराइवल और भारतीयों के लिए वीजा-फ्री एंट्री से भारतीय यात्रियों के ट्रैवल प्लान को बढ़ावा मिलता है।

थॉमस कुक इंडिया के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने कहा कि अच्छी बात यह है कि श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड जैसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन ने भारतीय के लिए वीजा फ्री एंट्री की घोषणा की है। इससे इन देशों में घूमने के लिए जाने वाले और पूछताछ करने वाले यात्रियों की संख्या में उछाल आया है।

थॉमस कुक इंडिया के शेयरों का हाल

थॉमस कुक इंडिया के शेयरों ने पिछले 6 महीने में करीब 35 फीसदी का रिटर्न दिया है। लेकिन, पिछले एक साल में निवेशकों को कंपनी से 238 फीसदी का रिटर्न मिला है। फिलहाल, इसकी शेयर प्राइस 211.25 रुपये है। कंपनी के तिमाही नतीजे भी काफी शानदार रहे। थॉमस कुक इंडिया का रेवेन्यू पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही 27 फीसदी बढ़ा और यह 1,664 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

क्या कहती हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन्म कुण्डली

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

2024 में मोदी पुनः बनेंगे प्रधानमंत्री

भीलवाड़ा। ज्योतिषीय गणनानुसार और लोकसभा चुनाव 2024 में 4 जून को किसके हाथ मजबूत होंगे एवं कौन भारतवर्ष का भावी भाग्य विधाता होगा, जैसे अनेको प्रश्न जनमानस के मन में उठ खड़े होते हैं। तो आईये ज्योतिष गणनानुसार जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति, भारतवर्ष, भाजपा एवं मोदी के सितारे क्या दर्शातें हैं।

ग्रहों की गणनानुसार एनडीए गठबन्धन को 340 से अधिक सीटे होने के योग बन रहे हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को 232 से 290 तक सीटे प्राप्त होने के प्रबल संकेत बन रहे हैं। इधर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्म 17 सितम्बर 1950 को प्रातः 11:00 बजे गुजरात के बड़नगर में हुआ था। और इनके लग्नानुसार जन्म वृश्चिक राशि एवं वृश्चिक लग्न में हुआ एवं लग्न व चन्द्र कुण्डली एक समान हैं। साथ ही लग्न एवं राशि स्वामी मंगल हैं जो कि एक अच्छा योग बनाता हैं, और उन्हे विशेष योग्य भी बनाता हैं। कुण्डली में लग्नेश मंगल एवं नवमेश चन्द्रमा के साथ विराजमान हैं। ऐसे में जब चन्द्रमा की दशा प्रारम्भ हुई और मोदी की राजनिती चमकने लगी तो साथ ही भारतीय जनता पार्टी में भी कार्यकर्ताओं में मोदी के प्रति वर्चस्व बढ़ने लगा और यह स्थित्ति इन्हें विशेष बनाती रही हैं।

-2024 लोकसभा चुनाव में ज्योतिष फलित।

ज्योतिष गणना के आधार पर मोदी के लग्न में मंगल एवं चन्द्रमा स्थित हैं एवं मंगल ग्रह यहाँ रोचक नामक पंच महापुरूष योग बना रहा हैं, एवं चन्द्रमा के साथ नीच भंग राजयोग भी बन रहा हैं। साथ ही मंगल ग्रह यहां छठे घर का स्वामी तथा तनु घर में विद्यमान होकर (स्वामी) हैं इस कारण मोदी सदैव शत्रुन्जय रहेंगे।

इधर सप्तमेश शुक्र कर्म स्थान में एवं साथ ही सुख भवन का स्वामी शनि भी कर्म स्थान में होने से मोदी न्यायप्रिय, प्रजाहितकारी होंगे, अन्याय के सख्त खिलाफ होंगे और प्रजाहित में नये कानून बनायेंगे।

गुरू और शुक्र केन्द्र में आमने सामने होने से इन दोनों ग्रहों के नैसर्गिक गुणों के कारण मोदी सामने वाले से वही व्यवहार करेंगे जैसा सामने वाला चाहता हैं।

गुरू के केन्द्र में होने से मोदी सर्वजन हित के संकल्प का कार्य करेंगे और भारतवर्ष की राजनीति में नये आयाम स्थापित करेंगे।

चतुर्थ भाव को शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं जिसके कारण मोदी न्याय एवं तर्कसंगत व्यवहार करेंगे।

एकादश भाव में सूर्य एवं बुध की युति से बुधादित्य योग होने से मोदी अपनी वाणी एवं व्यवहार शैली से प्रजा के चहेते रहेंगे भारत वर्ष के भावी भाग्य विधाता के रूप में माँ भारती की सेवा करते हुये समस्त विश्व पटल पर भारत को सर्वोच्च स्थान की प्राप्ति करायेंगे।

वर्तमान ग्रहदशा की स्थिति अनुसार मंगल की महादशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा 22 मई 2023 से 26 अप्रेल 2024 तक रहेगी फिर शनि की अन्तर्दशा मंगल में होगी एवं मंगल की महादशा वर्ष 2028 तक रहेगी। इस समयकाल में भारतीय सेना का सम्मान पूरे भारतवर्ष में बढ़ेगा एवं रोचक नामक पंच महापुरूष योग के कारण मोदी की छवि विश्व पटल पर एक महान निडर राजनायक के रूप में स्थापित होगी, एवं समस्त विश्व के नेता मोदी का नेतृत्व ग्रहण करेंगे। शुक्र ग्रह के कारण चुनोतिया तो असंख्य होगी लेकिन बृहस्पति के कारण पार पा लेंगे। 2024 में एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनने के बाद जून तक मोदी देशहित में ऐतिहासिक निर्णय लेंगें। क्यों की मंगल में शनि का अंतर रहेगा। जून 2025 से 2026 तक मोदी को कुछ स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्या आ सकती हैं। जिसमें विशेष रूप से पेट से सम्बन्धित रोग की प्रबल संभावना बनती हैं। अतः मोदी को विशेष ध्यान रखना होगा और ऐसी स्थिति में मोदी द्वारा अपने विशेष करीबी को भी सत्ता सौपनें के योग बनते हैं। साथ ही 2028 तक मोदी के निशकण्टक राजयोग बनता हैं विपक्ष एवं शत्रु निर्बल रहेंगे।

पण्डित योगेंद्र शर्मा बताते हैं कि पूर्व में वर्ष 2019 में उनके द्वारा भविष्यवाणी की गई थी की दूसरी बार भी मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे एवं इण्डिया से नाम बदलकर विश्व स्तर पर भारत नाम रखेंगे एवं भारतवर्ष की उन्नति एवं प्रगति के द्वार खुलेंगें और हिन्दू राष्ट्र की स्थापना भी होगी।

फिलहाल आपके मंगल स्वास्थ्य की अभिलाषा एवं भावी भारतवर्ष के निर्माण के रूप में आपके दिर्घायु जीवन की ईश्वर से मंगलमय प्रार्थना करते हैं।

पण्डित योगेंद्र शर्मा ने बताया कि उक्त ग्रहों की गणना करने के बाद आये फलादेश के मूल प्रपत्र को लिफाफे में बन्द करके मोदी के लिए उनके आवास नई दिल्ली हेतु स्पीडपोस्ट भी करवाया हैं। माँ ललिताम्बिका ज्योतिष केन्द्र आचार्य योगेंद्र शर्मा, भूणास, कारोई। प्रधान पण्डित श्री बाबाधाम शक्ति पीठ भीलवाड़ा।

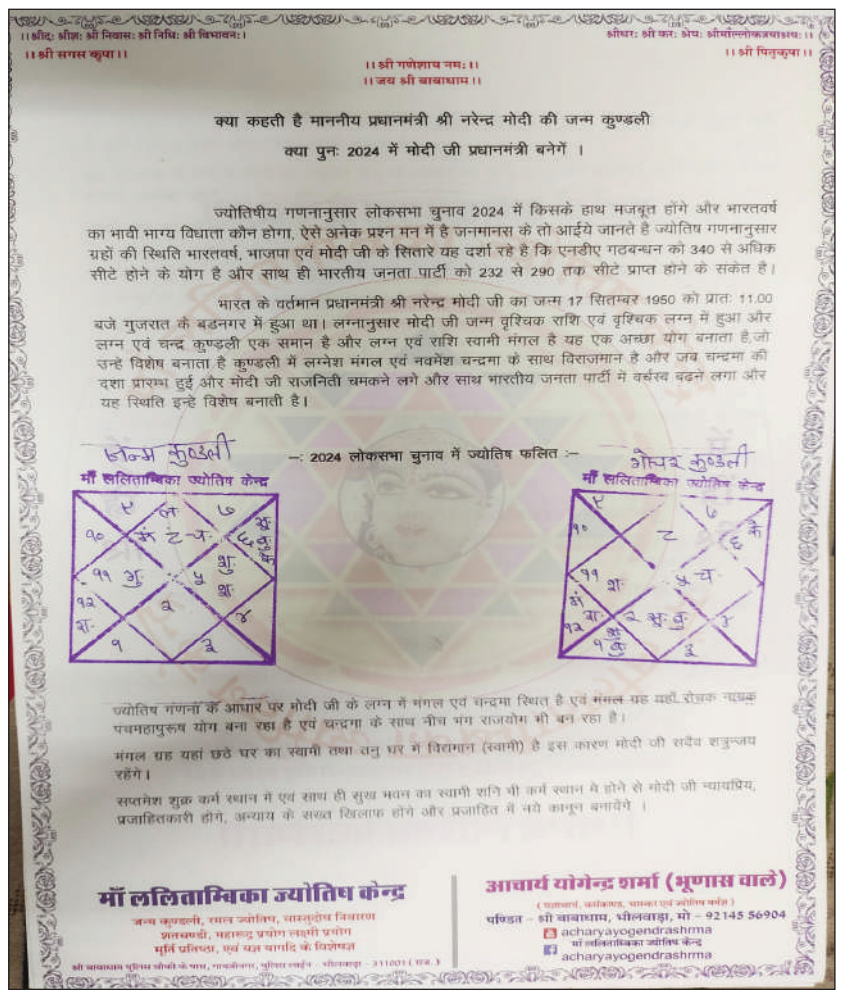

'पत्नी और बेटा करता है मारपीट, खाना भी नहीं देते', कोर्ट पहुंची भरतपुर के पूर्व राजपरिवार की लड़ाई

विश्वेन्द्र ने पत्नी दिव्या एवं बेटे अनिरूद्ध के खिलाफ उपखंड अधिकारी ट्रिब्यूनल में प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में विश्वेन्द्र ने आरोप लगाया कि पत्नी व बेटा उन्हें लोगों से मिलने नहीं देते हैं। घर (मोती महल) छोड़ने को मजबूर कर दिया।इस कारण उन्हें कभी होटल तो कभी अन्य किसी स्थान पर रहना पड़ रहा है। बता दें कि दिव्या सिंह पूर्व में सांसद व विधायक भी रही हैं।

जयपुर। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री और भरतपुर पूर्व राजपरिवार के सदस्य विश्वेन्द्र सिंह ने अपनी पत्नी व बेटे पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। कहा कि ये लोग उनको भरपेट भोजन भी नहीं देते हैं। दोनों ने उनके कपड़े जलाकर कुएं में फेंक दिए हैं। पत्नी व बेटे के साथ रहना अब संभव नहीं है। उन्होंने पत्नी व बेटे से वरिष्ठ नागरिक के रुप में पांच लाख रुपये भरण-पोषण भत्ता मांगा है।

विश्वेन्द्र ने पत्नी दिव्या एवं बेटे अनिरूद्ध के खिलाफ उपखंड अधिकारी ट्रिब्यूनल में प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में विश्वेन्द्र ने आरोप लगाया कि पत्नी व बेटा उन्हें लोगों से मिलने नहीं देते हैं। घर (मोती महल) छोड़ने को मजबूर कर दिया। इस कारण उन्हें कभी होटल तो कभी अन्य किसी स्थान पर रहना पड़ रहा है। बता दें कि दिव्या सिंह पूर्व में सांसद व विधायक भी रही हैं।

शारीरिक और मानसिक यातना का आरोप

विश्वेन्द्र ने आरोप लगाया कि पत्नी व बेटा उन्हें संपत्ति के लिए उन्हें जान से मारना चाहते हैं। बताया कि वह हार्ट के मरीज हैं और उन्हें दो स्टंट डाले जा चुके हैं। दो बार कोरोना होने के बावजूद पत्नी व बेटे ने किसी तरह की कोई मदद नहीं की थी। विश्वेन्द्र ने कहा, पिता की वसीयत में मिली संपत्तियों पर मेरा अधिकार है, पत्नी व बेटे ने दस्तावेज फाड़ दिए। पूर्व रियासतकालीन मोती महल में रहने के दौरान मुझे एक कमरे में कैद कर दिया था। मुश्किल से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। विश्वेन्द्र ने बताया कि पत्नी के पास नौ करोड़ के जेवरात और कई अन्य कीमती सामान हैं। पत्नी की वार्षिक पेंशन छह लाख रुपये प्रतिवर्ष और बेटे की आय 34 लाख वार्षिक है। पत्नी बोली, इन्होंने तो कारपेट तक बेच दिया दिव्या अपने पति विश्वेन्द्र के आरोपों को गलत बताती हैं। उनका कहना है कि विश्वेन्द्र ने तो प्राचीन कारपेट तक बेच दिया। एक-एक कर मथुरा, पुष्कर, दिल्ली व भरतपुर की कई संपत्ति बेच दी। मैं मोती महल नहीं बिकने दूंगी। मेरे साथ 33 साल से क्या हुआ, यदि मैं मुंह खोल दूं तो मामला सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगा। बेटे अनिरूद्ध ने कहा, पिता हमें बदनाम कर रहे हैं।

हिमाचल और उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगी जंगल में आग की घटनाएं, अग्निशमन कर्मियों की छुट्टियां रद; अब तक करोड़ों रुपये का हुआ नुकसान

पिछले पांच दिन में 422 आग की घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें 20 मामले घरों की आग जबकि शेष वन की आग के हैं। इससे करीब 1.70करोड़ रुपये की क्षति हो चुकी है। वहींउत्तराखंड में पिछले 24घंटे के भीतर जंगल की आग की छह घटनाएं सामने आई हैं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में गर्मी तेज होने से आग की घटनाएं बढ़ने की आशंका है।

नईदिल्ली। मौसम की तपिश बढ़ने के साथ हिमाचल और उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। हिमाचल में अधिकतर घटनाएं चीड़ के जंगलों में सामने आई हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि लोग जंगलों में सफाई के दौरान घास के लिए झाड़ियों को जलाते हैं, इस वजह से जंगलों में आग फैली है।

पिछले पांच दिन में 422 आग की घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें 20 मामले घरों की आग, जबकि शेष वन की आग के हैं। इससे करीब 1.70 करोड़ रुपये की क्षति हो चुकी है। वहीं, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के भीतर जंगल की आग की छह घटनाएं सामने आई हैं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में गर्मी तेज होने से आग की घटनाएं बढ़ने की आशंका है। वन की आग की चपेट में घर व पशुशालाएं भी आ रही हैं।

अग्निशमन कर्मियों की छुट्टियों को किया गया रद

इसके अतिरिक्त वन्य जीव भी जल कर मर रहे हैं। हिमाचल में अग्निशमन कर्मियों की छुट्टियों को रद किया गया है। हिमाचल में रविवार को ऊना जिले के अंब उपमंडल के ठठल, अंब बेला, कलरूही, बणे दी हट्टी, भद्रकाली व पाबड़ा थप्पलां में हुई आग की घटनाओं में वन संपदा का नुकसान हुआ है। कुटलैहड़ क्षेत्र में रविवार शाम करीब चार बजे मलांगड़ पंचायत के अमरेहड़ा गांव में मधुमक्खी पालक द्वारा रखे गए 50 डब्बे आग की भेंट चढ़ गए। इस घटना में मधुमक्खी पालक दुनी चंद को डेढ़ से दो लाख रुपये तक का नुकसान हुआ है।

उधर, चिंतपूर्णी क्षेत्र के जंगलों में एक सप्ताह से आग की घटनाएं हो रही हैं। शनिवार रात को सिरमौर जिले के जंगलों में अचानक भड़की आग से भी काफी नुकसान हुआ है।

आग बुझाने में आ रही समस्या

वनों की आग को बुझाने में सबसे बड़ी समस्या सड़क न होना है। इससे वहां तक अग्निशमन विभाग का वाहन नहीं पहुंच पाता। इसके अतिरिक्त कई जगह आग की घटनाएं होने से सभी जगह पहुंच पाना भी संभव नहीं हो पाता। वन विभाग ने वन रक्षक व राखे भी तैनात किए हैं। इसके साथ ही आग बुझाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कमेटियां भी हैं, लेकिन उनके प्रयास भी कम पड़ रहे।

उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर जंगल की आग की छह घटनाएं

उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। रविवार को 24 घंटे के भीतर छह नई घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें साढ़े चार हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। फायर सीजन में अब तक कुल 1098 घटनाओं में 1484 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क होने के कारण जंगलों में आग का खतरा बना हुआ है।

वन विभाग का दावा है कि ज्यादातर क्षेत्रों में आग पर काबू पा लिया गया है। साथ ही जंगलों में आग लगाने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई जारी है। अब तक इस सीजन में जंगल में आग लगाने पर वन संरक्षण अधिनियम और वन अपराध के तहत 422 मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। वहीं, वन विभाग की ओर से मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

अनचाही कॉल्स से हो गए हैं परेशान? नहीं आएंगे क्रेडिट कार्ड, लोन वाले फर्जी कॉल;

उपभोक्ता मामले का मंत्रालय अनचाहे कॉल को लेकर नियम बनाने जा रहा है और कॉल सेंटर प्रमोशनल कॉल करने वालों के खिलाफ गैर कानूनी व्यापार के तहत कार्रवाई करने का प्रविधान लाया जा सकता है। उन पर भारी जुर्माने की व्यवस्था होगी। एक और तैयारी यह चल रही है कि जिन नंबर से काफी अधिक कॉल आ रहे हैं उनकी जांच की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

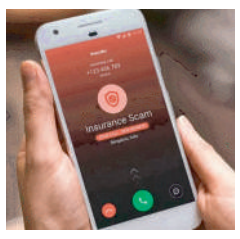

नई दिल्ली। अनचाहे कॉल से मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है और जल्द ही कॉलर नेम प्रेजेंटेशन (सीनैप) का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। दूसरी तरफ इस प्रकार के कॉल के रोकने के लिए सरकार भारी जुर्माना के प्रविधान के लिए भी नियम लाने की तैयारी में है। इसके अलावा वैसे नंबर पर भी नजर रखी जाएगी जिनसे दो-तीन घंटे में काफी अधिक संख्या में कॉल हो रहे हो।

टेलीकॉम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीनैप का पायलट शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है और जल्द ही पायलट शुरू हो रहा है। पायलट देश के किसी खास इलाके में किया जाएगा। सीनैप से यह फायदा होगा कि कॉल आने पर नंबर के साथ नाम भी पता चलेगा। इससे कॉल उठाने में मदद मिलेगी। कमर्शियल व मार्केटिंग कॉल के लिए अलग नंबर के सीरीज जारी होंगे, ताकि उपभोक्ता को पता रहे कि इस कॉल को उठाना है या नहीं।

वहीं, उपभोक्ता मामले का मंत्रालय भी अनचाहे कॉल को लेकर नियम बनाने जा रहा है और कॉल सेंटर, प्रमोशनल कॉल करने वालों के खिलाफ गैर कानूनी व्यापार के तहत कार्रवाई करने का प्रविधान लाया जा सकता है। उन पर भारी जुर्माने की व्यवस्था होगी। एक और तैयारी यह चल रही है कि जिन नंबर से काफी अधिक कॉल आ रहे हैं, उनकी जांच की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अभी अनचाहे कॉल के नंबर को ब्लॉक करने की सुविधा है, लेकिन मार्केटिंग वाले कॉलर्स फिर दूसरे नंबर से कॉल करने लगते हैं। इसलिए जिन नंबर से दो-चार घंटे में काफी अधिक कॉल होता दिखेगा, उनकी जांच होगी। टेलीकॉम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि चोरी के मोबाइल को ब्लाक करने से लेकर सिम कार्ड के गलत उपयोग के मामले में संचार साथी पोर्टल की मदद से लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब अनचाहे कॉल पर पूरी तरह ले लगाम लगाने की तैयारी चल रही है।

हृदय घात से बचाव के लिए 1000 महेश आरोग्य किट चित्तौड़गढ़ में वितरित किये

दक्षिण राजस्थान माहेश्वरी सभा का छठ्ठा शिविर आयोजित

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा द्वारा नौ जिलों में सर्व समाज के लिए हृदय घात से बचाव के लिए महेश आरोग्य किट का वितरण निशुल्क किया जा रहा है चित्तौड़गढ़ में अप्सरा टॉकीज चौराहे पर आयोजित निशुल्क महेश आरोग्य किट वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष राधेश्याम चेचानी,प्रदेश संगठन मंत्री ओम गट्याणी, प्रदेश कार्यालय मंत्री देवेंद्र सोमानी विशिष्ट अतिथि थे

चित्तौड़गढ़ में अप्सरा टॉकीज के सामने पहला शिविर लगाकर हृदय घात से बचाव के लिए निशुल्क1000 महेश आरोग्य किट वितरण किए गए

कार्यक्रम किट प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस अवसर पर अनिल ईनाणी का तदर्थ समिति संयोजक ,मुकेश गग्गड प्रदेश उपाध्यक्ष, राकेश जैथलिया पूर्व प्रदेश मंत्री, अशोक कबरा पुर्व जिला अध्यक्ष ,राकेश मंत्री नगर अध्यक्ष, शांतिलाल भराडिया, नानालाल भुण्डा, सत्यप्रकाश जेथलिया, धर्मेंद्र सोमानी ,शैलेंद्र झवर कैलाश मंत्री उपस्थित थे शुभारंभ के अवसर पर 1000 महेश आरोग्य किट का अतिथियों ने वितरण कियाकम आयु वर्ग के अचानक हार्ट अटैक आने पर मिलने वाले 30 मिनट के गोल्डन टाइम में प्राथमिक उपचार के लिए माहेश्वरी समाज द्वारा पहली बार पहल कर महेश आरोग्य किट निःशुल्क वितरण करने का प्रयास चित्तौड़गढ़ में किया गया

दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा का छठ्ठा शिविर लगेगा रीको एरिया में 20 कोभीलवाड़ा दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा का छठ्ठा महेश आरोग्य किट वितरण शिविर रीको एरिया में 20 मई को प्रातः 10 बजे सेव लोन सल्ज प्राइवेट लिमिटेड में आयोजित किया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम चेचानी ने बताया कि आगामी दिनों उदयपुर राजसमंद एवं निंम्बाहेड़ा में महेश आरोग्य किट वितरित किए जाएंगे महेश आरोग्य किट के पांच शिविर भीलवाड़ा में आयोजित किए गए एवं एक चित्तौड़गढ़ में 19 मई को आयोजित किया गया

साल में एक लाख रुपये, 10 किलो मुफ्त अनाज, नौकरियां... अखिलेश और तेजस्वी भी अपनी रैलियों में कर रहे कांग्रेस के चुनावी वादों का इस्तेमाल

कांग्रेस के बड़े वादों को सपा राजद झामुमो से लेकर शिवसेना यूबीटी जैसी पार्टियों के नेता न केवल चुनावी सभाओं में इसे आइएनडीआइए गठबंधन के वादे के रूप में पेश कर रहे बल्कि इन घोषणाओं पर भाजपा के हमले पर जवाबी पलटवार भी कर रहे हैं। कांग्रेस के चुनावी वादों को उसके सहयोगी दल भी हाथोंहाथ लपक रही है।

नईदिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए अब दो चरणों के बाकी बचे प्रचार में सियासी मुद्दों की गरमागरमी के बीच विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए में शामिल कांग्रेस के कई सहयोगी दल उसके चुनाव घोषणापत्र में किए वादों को अपने प्रचार अभियान के दौरान जोर-शोर से उठाने से परहेज नहीं कर रहे।

महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब महिलाओं को एक लाख रुपए सालाना, युवाओं को अप्रेंटिसशिप अधिकार के साथ एक साल के लिए एक लाख रुपए तो केंद्र सरकार की नौकरियों में खाली 30 लाख पदों को सरकार में आते ही भरने की प्रक्रिया शुरू करने के कांग्रेस के बड़े वादों को सपा, राजद, झामुमो से लेकर शिवसेना यूबीटी जैसी पार्टियों के नेता न केवल चुनावी सभाओं में इसे आइएनडीआइए गठबंधन के वादे के रूप में पेश कर रहे बल्कि इन घोषणाओं पर भाजपा के हमले पर जवाबी पलटवार भी कर रहे हैं।

भाजपा पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के सहयोगी

कांग्रेस के चुनावी वादों की सबसे नई सूची में शामिल गरीबों को 10 किलो मुफ्त अनाज देने के ताजा एलान को भी उसके सहयोगी दलों ने हाथोंहाथ लपक लिया है। राजद से लेकर शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने इस वादे का पूरा समर्थन करते हुए भाजपा के इस पर उठाए जा रहे सवालों को खारिज कर दिया है। ऐसे वादों से देश के आर्थिक संकट में घिरने से लेकर दिवालिया होने के पीएम मोदी के आरोपों को खारिज करने में कांग्रेस के सहयोगी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं।

भाजपा की यह सोच ही दर्शाती है कि वह किसकी हितैषी है

राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने सत्ताधारी दल के नेतृत्व की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए का बैंकों का कर्ज माफ कर देती है तो इससे देश पर आर्थिक संकट नहीं आता। मगर गरीब महिलाओं के खाते में साल में एक लाख रुपए दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था के लिए संकट खड़ा हो जाएगा भाजपा की यह सोच ही दर्शाती है कि वह किसकी हितैषी है। गरीबों को 10 किलो मुफ्त राशन देने के वादे का तेजस्वी यादव भी समर्थन कर रहे हैं।

भाजपा पर हमले कर रहे हैं राहुल और अखिलेश

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी केंद्र में 30 लाख नौकरियों की भर्ती, अग्निवीर योजना बंद करने से लेकर महालक्ष्मी योजना का अपनी चुनावी सभाओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष जिक्र करने से गुरेज नहीं कर रहे। महिलाओं और अप्रेंटिसशिप करने वाले युवाओं के खाते में सालाना एक लाख रुपए ट्रांसफर करने के राहुल गांधी के खटाखट-खटाखट शब्द का तो अखिलेश अपनी चुनावी सभाओं में भरपूर इस्तेमाल कर भाजपा पर हमले कर रहे हैं।

महाराष्ट्र में चुनावी पारा चरम पर है

महाराष्ट्र में चुनावी पारा चरम पर है जहां शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे अपनी सभाओं में कांग्रेस के इन बड़े वादों को आइएनडीआइए के वादे के रूप में पेश करते हुए इन्हें देश के समग्र विकास से जोड़ रहे हैं। वहीं उनकी पार्टी के मुखर नेता संजय राऊत और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी न केवल कांग्रेस के वादों की सार्वजनिक तरफदारी कर रहे बल्कि भाजपा पर आक्रामक पलटवार करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं।

राहुल गांधी के चुनावी एलानों का समर्थन कर रही है NCP

शरद पवार की एनसीपी तो खुलकर राहुल गांधी के चुनावी एलानों का समर्थन कर रही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर भले कांग्रेस के वादों का जिक्र करने से बच रहीं मगर अग्निवीर भर्ती बंद करने से लेकर नौकरी-रोजगार देने जैसे उसकी घोषणाओं को अपने चुनावी वादों में शामिल किया है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023